Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
Published from Ranchi
Ranchi ● Sunday, 21 July 2024 ● Year : 01 ● Issue : 183 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

सुविचार

घाव पर बार-बार चोट लगती है, अन्न की कमी होने पर भूख बढ़ जाती है, विपत्ति में बैर बढ़ जाते हैं- विपत्तियों में अनर्थ बहुलता होती है।

-अज्ञात

Disha Patani Aces Double Back...

SHARE

सेंसेक्स	:	80,604.65
निफ्टी	:	24,530.90

SARAFA

सोना	:	6,950
चांदी	:	96.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा

NEW DELHI : यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे के बाद सामाजिक और धार्मिक कामों पर ध्यान देंगे। उन्होंने 14 दिन पहले अपना इस्तीफा कार्मिक विभाग (डीओपीटी) को भेजा था, इसकी जानकारी 20 जुलाई को सामने आई है। अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। उनका कार्यकाल मई 2029 तक था। उन्होंने 16 मई 2023 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। इस्तीफे की जानकारी आने के बाद मनोज सोनी ने कहा है कि उनका इस्तीफा ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के विवादों और आरोपों से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। वहीं, कांग्रेस लीडर और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने चेयरमैन के इस्तीफे पर कहा है कि उन्हें यूपीएससी से जुड़े विवादों के बीच पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक लगातार संवैधानिक बॉडी की शुचिता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

नए क्रिमिनल कानूनों पर केंद्र सरकार को नोटिस

CHENNAI : मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तीन नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। राज्य की डीएमके सरकार ने इन कानूनों को अधिकारातीत और असंवैधानिक बताने की याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। डीएमके के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी आर एस भारती की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई जस्टिस एस एस सुंदर और एन सेंथिल कुमार की डिविजन बेंच के सामने हुई। बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है। दरअसल, 1 जुलाई से तीन नए कानून- भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। इन्होंने इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (सीआरपीसी) और इंडियन एविडेंस एक्ट (आईईए) की जगह ली है।

गोवा के समुद्र में कार्गो शिप में लगी आग

NEW DELHI : दक्षिण-पश्चिम गोवा के समुद्र में मेर्स्क फ्रैंकफर्ट नाम के कार्गो शिप में 19 जुलाई की दोपहर आग लग गई। आग लगने के बाद जहाज बहकर कर्नाटक के पास कारवार पहुंच गया। यहां इंडियन कोस्ट गार्ड्स (आईसीजी) के तीन जहाज आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। शिप का एक क्रू मेंबर लापता है। आईसीजी ने आग को फैलने से तो रोकने में सफलता हासिल की है, लेकिन दक्षिण-पश्चिमी हवाएं, भारी लहरों और खराब मौसम के कारण आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप पर शॉट सर्किट की वजह से लगी आग की वजह से विस्फोट हुआ। आग तेजी से डेक पर फैली गई।

इंडियन आर्मी ने जम्मू में तैनात किए 500 स्पेशल पारा कमांडो

AGENCY SRINAGAR : बढ़ते आतंकी हमलों के मद्देनजर जम्मू में भारतीय सेना ने लगभग 500 पारा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। रक्षा सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50-55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आतंकियों का समर्थन करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 17 जुलाई को केरन सेक्टर में मारे गए आतंकियों के पास से स्टेयर एयूजी असॉल्ट राइफल मिली है। यह एक ऑस्ट्रेलियाई राइफल है। इसके चैंबर में 5.5645 मिमी का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। इस राइफल को 1960 के दशक में स्टेयर-डेमलर-पुच द्वारा डिजाइन किया गया था। अब इसे स्टेयर आर्म्स जीएमबीएच एंड कंपनी केजी द्वारा बनाया जा रहा है।

पाक के 50-55 आतंकियों की मौजूदगी का शक, टेरर नेटवर्क एक्टिव कर दहशत फैलाना मकसद

हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आए हैं आतंकी

रक्षा सूत्रों के मुताबिक, जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और उपकरण हैं। सेना इन आतंकियों की तलाश और उन्हें खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी जम्मू जा रहे हैं। वे सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू में बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की घटनाओं को लेकर मीटिंग करेंगे। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सेना पहले ही 3500 से 4000 सैनिकों की अपनी ब्रिगेड उतार चुकी है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही एक काउंटर-टेररिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो और डेल्टा फोर्सेज के साथ-साथ राष्ट्रीय राइफल्स की दो फोर्सेज शामिल हैं।

जैश-लश्कर का 20 साल पुराना नेटवर्क सक्रिय

जम्मू रीजन में सेना ने 20 साल पहले पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जिस लोकल नेटवर्क को सख्ती से निष्क्रिय कर दिया था, वो पूरी ताकत से फिर एक्टिव हो गया है। पहले ये लोग आतंकियों का सामान ढोने का काम करते थे, अब उन्हें गांवों में ही हथियार, गोला बारूद और खाना-पीना दे रहे हैं। बीते दिनों जिन 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, उन्होंने पूछताछ में इसके सुराग दिए हैं। यह नेटवर्क जम्मू के 10 में से नौ जिलों राजौरी, पुंछ, रियासी, ऊधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और रामबन में जम चुका है।

370 हटाने के बाद टारगेट करने की रणनीति

जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य के मुताबिक, आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया था। उसने दो साल में इस नेटवर्क को सक्रिय किया। इन्हीं की मदद से आतंकियों ने 2020 में पुंछ और राजौरी में सेना पर बड़े हमले किए। फिर ऊधमपुर, रियासी, डोडा और कठुआ को निशाने पर लिया। 2020 तक जम्मू रीजन में काफी सुरक्षा बल तैनात था। गलवान एपिसोड के बाद चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए यहां की सेना को हटाकर लद्दाख भेज दिया गया।

धुर्वा में भाजपा के 26000 कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

अमित शाह बोले- झारखंड में पूर्ण बहुमत की बनाएंगे सरकार

PHOTON NEWS RANCHI : शनिवार को रांची के प्रभात तारा मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 हजार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज बताकर जा रहा हूं कि झारखंड में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ह्यइंडीह्न गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भाजपा का समर्थन किया। 60 साल के बाद तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री चुना गया है। झारखंड की जनता ने 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। इस चुनाव में हम झारखंड में 9 सीटें जीते हैं। यह बताता है कि आने वाले दिनों में झारखंड में सरकार किसकी बनने वाली है। अमित शाह ने जेएमएम-कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है, लेकिन पराजय के बाद अहंकार आया हो यह पहली बार देख रहा हूं। देश में सरकार किसी और की बनी, चुनाव कोई और जीता। लेकिन, अहंकार कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने राहुल गांधी को देखा है, इतना अहंकार कोई दो-तिहाई बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता।

कांग्रेस और झामुमो पर साधा निशाना, राहुल को बताया अहंकारी

- चुनाव जीती भाजपा, अहंकार कांग्रेस को आया
- 10 साल में नक्सलवाद को मोदी ने कर दिया समाप्त
- हेमंत सरकार को आदिवासियों की चिंता नहीं

रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी व अन्य वरिष्ठ नेता।

सुरक्षा में चूक, काफिले में घुसा बाइक सवार

शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक सामने आई है। रांची एयरपोर्ट से अमित शाह जैसे ही बिरसा चौक के लिए निकले, एक बाइक सवार उनके काफिले में घुस गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि बाइक सवार काफिले का हिस्सा नहीं था। हालांकि वह तेज गति से गाड़ी चला रहा था और काफिले का पीछा कर रहा था, इसलिए हमने उसे हिरासत लिया है। बता दें कि भाजपा की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक का आयोजन रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। काफिले में घुसे बाइक सवार दोनों युवकों की पहचान हो गई है। एक युवक का नाम अंकित और दूसरे का मोहित है।

देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं को मिलेगी हर सुविधा : हेमंत

PHOTON NEWS DEOGHAR : शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा, सुरक्षा और सुलभ जलार्पण के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी विभागों को पुख्ता तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि श्रावणी मेले के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद वे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे सावन महीने में दुम्मा से लेकर बाबा मंदिर तक पूरे मेला क्षेत्र में प्रशासन और सरकार की सारी सुविधाएं 24 घंटे सातों दिन रहेंगी। इसके लिए पुख्ता तैयारी की गई है। देवघर के बाबा धाम जितने भी श्रद्धालु आएंगे, वे सुखद अनुभूति के साथ सुलभ जलार्पण करके अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। यही सरकार और प्रशासन का उद्देश्य है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ से यही कामना है कि हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेला 2024 सफलतापूर्वक संचालित हो और जितने भी श्रद्धालु बाबा धाम आएं, सभी सकुशल जलार्पण के बाद अपने घर को पहुंच जाएं। रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डेमोग्राफी चेंज को लेकर दिए गए बयान पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राजनीतिक बयानों का जवाब अभी देना नहीं चाहते हैं। समय आने पर उनका भी जवाब देंगे।

- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संग की श्रावणी मेले की तैयारी की समीक्षा
- सुखद अनुभूति के साथ बाबा की पूजा कर लौटेंगे श्रद्धालु
- समय आने पर राजनीतिक बयानों का देंगे जवाब

पत्नी संग की बाबा की पूजा-अर्चना

देवघर आगमन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपत्नीक कामनालिंग बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना की। बाबा मंदिर में तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूरे वैदिक रीति-रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ संकल्प कराया गया। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने सपत्नीक बाबा मंदिर के गर्भगृह पहुंचकर पवित्र द्वादश ज्यार्तिलिंग का जलाभिषेक किया और मत्था टेककर मंगलकामना की। इसके अलावा पूजा-अर्चना बाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्मृति चिह्न भेंट स्वरूप प्रदान किया।

'सुप्रीम' आदेश पर नीट-यूजी एग्जाम का सिटी व सेंट्रलाइज्ड रिजल्ट जारी

गोधरा और हजारीबाग सेंटर्स से कोई टॉपर नहीं

AGENCY NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने शनिवार, 20 जुलाई को नीट-यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटरवाइज रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हुआ। इसमें कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई है। खास बात ये है कि विवादास्पद गोधरा और हजारीबाग सेंटर्स से कोई भी कैंडिडेट टॉपर नहीं है। गोधरा के जय जलराम स्कूल के सेंटर से 2 स्टूडेंट ने 600 नंबर स्कोर किए हैं। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को 600 से ज्यादा नंबर नहीं मिले हैं। परीक्षा हजारीबाग के 5 एग्जाम सेंटर्स पर हुई थी। सीबीआई ने हजारीबाग से राजकुमार उर्फ राजू को 16 जुलाई को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग के भी किसी एग्जाम सेंटर से टॉपर नहीं निकला है।

एनटीए ने माना- दोनों जगह गड़बड़ी हुई, सीबीआई ने गिरफ्तारियां भी कीं

4,750 सेंटर्स पर 5 मई को हुई थी परीक्षा

18 जुलाई को नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। इस दौरान एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में गोधरा और पटना के एग्जाम सेंटर्स पर गड़बड़ी की बात मानी है। नीट परीक्षा 4,750 सेंटर्स पर 5 मई को हुई थी। इसमें 24 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार किया था। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था- काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा। यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी।

ममता बनर्जी की टीएमसी खर्च में सबसे बड़ी पार्टी

NEW DELHI : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) खर्च के मामले में देश की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पार्टी की कमाई 333.45 करोड़ रुपये थी, जबकि खर्च 181.1 करोड़ रुपये किए। वहीं, कमाई के मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) टॉप पर रही। 2022-23 में पार्टी की कमाई 737 करोड़ रुपये रही, जबकि खर्च के 57.47 करोड़ रुपये रहा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी रफकांग्रेस कमाई के मामले में तीसरे और खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर रही। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में देश की 57 में से 39 रीजनल पार्टियों की कमाई और खर्च का ब्योरा जारी किया है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, सभी पार्टियों को अपनी सालाना आय-व्यय की रिपोर्ट आयोग का सौंपनी होती है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 39 क्षेत्रीय पार्टियों की कुल आय एक हजार 740 करोड़ रुपये थी जो पिछले साल 2021-22 की तुलना में 20 करोड़ रुपये अधिक है। वहीं पार्टियों का खर्च केवल 481 करोड़ रुपये ही रहा। यानी कमाई के मुकाबले खर्च एक चौथाई से भी कम है।

जर्नल साइंस एडवांसेज में छपी खबर को बताया भ्रामक

कोरोना में मौतों की रिपोर्ट को केंद्र ने किया खारिज

AGENCY NEW DELHI : देश में कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों को लेकर जर्नल साइंस एडवांसेज में छपी रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अनुमानों के आधार पर जर्नल साइंस एडवांसेज में 2020 में कोरोना से अत्यधिक मृत्यु दर को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्ट खामियों से भरी और असंगत तथा अस्पष्ट है। भारत में 2019 की तुलना में 2020 में 11.9 लाख मौत बताई गई, जबकि वास्तविक आंकड़े इससे काफी कम हैं। अध्ययन के निष्कर्षों और स्थापित कोरोना मृत्यु दर पैटर्न के बीच विसंगतियां इसकी विश्वसनीयता को और कमजोर करती हैं। यह अध्ययन भारत की मजबूत नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) को स्वीकार करने में असफल रहा है, जिसने 2020 में मृत्यु पंजीकरण में पर्याप्त वृद्धि (99 प्रतिशत से अधिक) दर्ज की, जो केवल महामारी के लिए जिम्मेदार नहीं है।

अत्यधिक मृत्यु दर की बात खामियों से भरी, असंगत और अस्पष्ट

अस्थिर अनुमानों पर आधारित निष्कर्ष

नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने अपने एक बयान में बताया कि कोरोना महामारी में 2020 में अत्यधिक मृत्यु दर को दशातें हुए अकादमिक जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक पेपर के निष्कर्ष अस्थिर और अस्वीकार्य अनुमानों पर आधारित हैं। लेखक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 एनएफएचएस-5 के विश्लेषण की मानक पद्धति का पालन करने का दावा करता है, लेकिन उनकी पद्धति में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण गलती यह है कि लेखकों ने जनवरी और अप्रैल 2021 के बीच एनएफएचएस सर्वेक्षण में शामिल घरों का एक सैंपल लिया है, 2020 में इन घरों में मृत्यु दर की तुलना 2019 से की है।

2020 में 12 लाख लोगों की मौत का दावा

भारत में कोरोना महामारी के पहले फेज में 12 लाख लोगों की जान गई थी। यह दावा कतर के मीडिया हाउस अलजजीरा ने 10 बड़े डेमोग्राफर्स (जनसंख्या की स्टडी करने वाले) और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के हवाले से किया है। बताया है कि 2020 में भारत में कोरोना के कारण हुई मौतें सरकारी आंकड़ों से 8 गुना ज्यादा थीं। भारत सरकार के मुताबिक, 2020 में कोरोना से करीब 1 लाख 48 हजार लोगों की मौत हुई थीं। जबकि नई रिपोर्ट के मुताबिक असल संख्या 12 लाख थी। ये आंकड़ा साइंस एडवांस पब्लिकेशन ने 19 जुलाई की रिपोर्ट में छापा है, जिसे भारत सरकार के 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएच) के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट में दिए आंकड़े डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों से भी डेढ़ गुना ज्यादा हैं। रिसर्च के मुताबिक, 2020 में उच्च-जाति के हिंदुओं की औसत जीवन दर में 1.3 साल की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, अनुसूचित जाति के लोगों की औसत जीवन दर में 2.7 साल की गिरावट आई। इसके अलावा भारत के मुस्लिम नागरिकों की जीवन दर पहले की तुलना में 5.4 साल घट गई।

बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा जारी

अब तक 105 लोगों की गई जान, पूरे देश में लगा कर्फ्यू

AGENCY NEW DELHI : बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबैदुल कादर ने 19 जुलाई देर रात से ही कर्फ्यू लागू करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि इसमें अब तक कुल 105 लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 978 भारतीय स्टूडेंट्स अपने घर लौट आए हैं।

- स्थिति नियंत्रित करने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा
- अगले आदेश तक ढाका यूनिवर्सिटी को किया गया बंद, भारतीय छात्र घर लौटे

कविता सेक्शन

डॉ कालिंदी बृजेश त्रिपाठी

01

राहें

द्वन्द्व चल रहा मन के भीतर
उसको विराम देना होगा
खुद से ही लड़ने की कोशिश
अब बन्द तुम्हें करना होगा।

जो धूप मिलेगी सफर में
तुझको
फिर भी चलते रहना होगा
राहें देता है कौन किसे ?
तुझे अपना मार्ग चुनना होगा।

राहें नहीं बदलते देखा
खुद को तुम्हें बदलना होगा
सभी फँसे हैं भीड़-भाड़ में,
आगे तुम्हें निकलना होगा...
आगे तुम्हें निकालना होगा ।।

02

तेरी यादों के छांव-तले

तुम लम्हा बन जाते मेरे,
हम वक्त तुम्हारा बन जाते
काश तूं गहरी नदिया होते,
हम धार तुम्हारा बन जाते...

तूं दिल की धड़कन बन जाते,
साया तेरा हम बन जाते
बिछड़ सके जो कभी नहीं
हम वह हमराही बन जाते...

खोकर तेरे ख्यालों में ही
लफ्जों को चुरा अब लेते हैं
अक्सर उन जज्बातों को ही
कागज पर हम लिख लेते हैं।।

03

बुनियादें

उम्मीदों की बुनियादें भी
आज हमारी जर्जर हैं
यहां जमीनें रिश्तों की
सारी की सारी बंजर हैं...

लेकर हजार गिले-शिकवे,
सब अपनों से ही रूठे हैं
ये नफरत की नदियां ही नहीं,
पूरा का पूरा समन्दर है...

राहें बहुत कठिन होंगी,
अविरल तुमको चलना होगा
जब लगे रोकने भीड़ तुम्हें,
धुन में अपने बढ़ना होगा।।

1. हमें अपना फीडबैक, सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए दिए गए बार कोड को स्कैन करें या मेल करें।
2. आप हमें अपनी रचनाएं, कविता या आलेख भी भेज सकते हैं। जिसे हम अपने आने वाले अंक पर प्रकाशित करेंगे।

SCAN ME

Email- thephotonnewsjharkhand@gmail.com

रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने का रोमांच

घुमक्कड़ की पाती

रणथंभौर नेशनल पार्क की जैव विविधता का कोई जवाब नहीं। यह बात मुझे स्टेशन पर उतरने के साथ ही पता चल गई थी। रणथंभौर किले और आसपास की पहाड़ियों व घाटियों के साथ मिलकर जो दृश्य उत्पन्न होता है, वह रणथंभौर उद्यान को एक समृद्ध पर्यटन स्थल बनाता है। 392 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह नेशनल पार्क विभिन्न सैकड़ों देशी-विदेशी प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास की जगह है।

संजय शेफर्ड
नई दिल्ली

राजस्थान स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क देश के सबसे अच्छे बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। इसकी वजह से इस जगह पर हर दिन हजारों सैलानी आते हैं और रणथंभौर की समृद्ध विरासत को देखना पसंद करते हैं। विंध्य और अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसे रणथंभौर को यहाँ मौजूद बाघों, वनस्पतियों और जीवों की विविधता के लिए जाना-जाता है। कहा जाता है कि इस अभ्यारण में बाघ को देखने की संभावना भारत के दूसरे बाघ अभ्यारण्यों की तुलना में काफी ज्यादा होती है। यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मुझे लगा कि इस जगह पर जाना ही चाहिए। मैंने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और रणथंभौर पहुँच गया।

रणथंभौर नेशनल पार्क की जैव विविधता का कोई जवाब नहीं। यह बात मुझे स्टेशन पर उतरने के साथ ही पता चल गई थी। रणथंभौर किले और आसपास की पहाड़ियों व घाटियों के साथ मिलकर जो दृश्य उत्पन्न होता है, वह रणथंभौर उद्यान को एक समृद्ध पर्यटन स्थल बनाता है। 392 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह नेशनल पार्क विभिन्न सैकड़ों देशी-विदेशी प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास की जगह है। सैलानी इस पार्क की सैर के दौरान यहाँ मौजूद जीव-जंतुओं और उनके प्राकृतिक आवास देख सकते हैं।

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास खंगालने के क्रम में एक सज्जन से मुलाकात हुई, जो बेंगलुरु से आए हुए थे। वह देश के तमाम नेशनल पार्क पर शोध कार्य कर रहे थे। उन सज्जन ने रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में मुझे काफी कुछ बताया। इस पार्क का इतिहास 1955 से शुरू होता है, जब इसे भारत सरकार ने सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। अठारह साल बाद यानी कि 1973 में इस पार्क को 'प्रोजेक्ट टाइगर' रिजर्व घोषित किया गया और 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। फिर साल 1991 में यह पार्क केलादेवी अभयारण्य और सवाई मान सिंह अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा बन गया।

रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया है और यह उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है।

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में तरह-तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। एक वन्यजीव प्रेमी के रूप में रणथंभौर नेशनल पार्क की यात्रा हमें रोमांच से भर देता है। इससे मेरी यह यात्रा हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस पार्क में काफी संख्या में वन्यजीव पाए जाते हैं। इस पार्क में जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों, वनस्पतियों और जीवों की कई विदेशी प्रजातियों के साथ दिव्य बाघों की प्रजाति भी पाई जाती है। इस पार्क में सरीसृपों, स्तनधारियों और पक्षियों की बड़ी संख्या पाई जाती हैं। इस जगह पर बर्ड वाचिंग के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। बाघों के अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए, कैराकल, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां और जंगली बिल्लियां पायी जाती हैं।

रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी करने का भी विकल्प मौजूद है। यदि आप अपनी यात्रा को मस्ती से भरी एडवेंचर यात्रा बनाना चाहते हैं, तो आपको रणथंभौर जंगल सफारी करना चाहिए। यह जंगल सफारी आपको इस जगह की विविधता को देखने समझने का भरपूर मौका देगी और आपकी यात्रा को रोमांच से भर देगी। जंगल सफारी के लिए जिप्सी, एसयूवी और कैंटर बुक करने की सुविधा यहाँ मौजूद है। सफारी के दौरान हर वाहन में ड्राईवर के अलावा एक गाइड होता है, जो आपको इस जगह के बारे में जानकारी देता है।

सफारी के लिए एडवांस बुकिंग करें

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी करने का मेरा भी मन था, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सैर करने के दौरान अगर आपकी जंगल सफारी करने की चाह है तो आपको पहले से इसे ऑनलाइन बुक कर लेना चाहिए। इससे यात्रा के दौरान आपका समय बचेगा और आप होने वाली परेशानी से भी बच जाएँगे। अगर किसी वजह से ऑनलाइन नहीं बुकिंग हो पाती है तो जिस जगह पर आप रुके हुए हैं वहाँ के होटल से आप सम्पर्क कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो तो एक दो घंटे पहले बुकिंग कार्यालय पहुंच जाएं।

इस जगह पर घूमने के लिए आएं तो आपको राजीव गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय भी जाना चाहिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय रणथंभौर की सबसे खास जगहों में शुमार की जाती है। यह भारत के प्राकृतिक इतिहास का चौथा क्षेत्रीय संग्रहालय है। इस लिहाज से इस जगह का महत्व का बढ़ जाता है। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करना है। इस संग्रहालय में कई दुर्लभ पौधों, जानवरों और भूविज्ञान से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय के कुछ सीमित हिस्सों तक ही पर्यटकों को जाने की अनुमति है। इस जगह पर राजस्थान की जैव विविधता की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें यहाँ के वनों और वन्यजीवों को आप देख सकते हैं।

अक्टूबर से दिसंबर तक बेहतर

हर पार्क की तरह रणथंभौर नेशनल पार्क भी अक्टूबर से लेकर जून तक खुला रहता है। इस जगह पर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का माना जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। आपके लिए रणथंभौर की यात्रा अक्टूबर से अप्रैल तक अनुकूल रहेगी। गर्मी के मौसम में वातावरण काफी गर्म होता है, जिसकी वजह से लोग कम आते हैं, लेकिन इस दौरान बाघों के स्पॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है। मानसून के मौसम में यह जगह और भी खूबसूरत हो जाती है, पर इस दौरान यह पार्क बंद रहता है।

ऐसे पहुंच सकते

रणथंभौर जाने के लिए सभी तरह के परिवहन की सुविधा मौजूद है। अगर आप हवाई जहाज से रणथंभौर नेशनल पार्क की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है, जो पार्क से सिर्फ 180 किमी दूर स्थित है। रेल द्वारा रणथंभौर नेशनल पार्क की यात्रा करने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर है, जो पार्क से बिल्कुल ही पास है। अगर आप सड़क मार्ग से रणथंभौर नेशनल पार्क जाने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि देश के सभी महत्वपूर्ण मार्गों से जुड़ा हुआ है और सवाई माधोपुर से सिर्फ 11 किमी की दूरी पर स्थित है।

इन्हें भी देखें

रणथंभौर में घूमने की कई अन्य जगहें भी मौजूद हैं। कई जगहें तो बेहद ही खास हैं, जहां आपको जाना ही चाहिए। जैसे कि रणथंभौर किला, गणेश त्रिनेत्र मंदिर, जोगी महल, पदम झील और सुरवल झील आदि। यह सभी पर्यटन स्थल बहुत ही अच्छे हैं और आपको सुखद अहसास कराएंगे। इन सब जगहों पर जाकर आपको इस जगह के सांस्कृतिक, एतिहासिक और प्राकृतिक महत्व को समझने में आसानी होगी।

PART - 1 ■ 70MM

सबसे अच्छे आदमी की तलाश करती 'परख'

विमल चंद्र पाण्डेय

वैसे तो बिमल रॉय को दो बीघा जमीन और बंदिनी जैसी फिल्मों के लिए अधिक माना और जाना जाता है, लेकिन 1960 में आई परख उनकी सबसे अलग स्वाद वाली फिल्म है, जिसमें आजादी के बाद के मोहभंग का उन्होंने इतने व्यंग्यपूर्ण ढंग से चित्रण किया है कि दिल कह उठता है, वाह ये है असली डायरेक्टर, जिसकी फिल्में एक दूसरे से इतनी अलग अलग हैं कि पता ही नहीं चलता कि सारी फिल्में एक ही व्यक्ति ने बनाई हैं।

'परख' कहने को तो एक गांव में सबसे ईमानदार यानी अच्छे आदमी की खोज करती है, लेकिन दरअसल यह आजादी के बाद के उस असंतुष्ट और लूट-खसोट वाले देश में एक अच्छे यानी ईमानदार आदमी की तलाश करती है और पाती है कि धर्म के नुमाइंदे, सामंतवाद के पुरोधा और समाजसेवा के शीर्ष सभी सिर से पांव तक सिर्फ लालच में डूबे हुए हैं। उम्मीद है तो सिर्फ युवाओं से। फिल्म की शुरूआत बिलकुल साधारण सी है और जरा भी ये आभास नहीं होने देती कि आगे यह व्यंग्य और एक से बढ़कर एक अनापेक्षित मोड़ों वाली कहानी साबित होने वाली है। निवारन पोस्ट मास्टर आर्थिक रूप में बहुत गरीब हैं, लेकिन बहुत गैरतमंद और ईमानदार इंसान हैं। उनके ऊपर काफी कर्जे हैं और इसी हालत में में उन्हें बेटी की शादी भी करनी है। उनका सहायक एक नया कर्मचारी हराधन है, जो इस बात पर खासा दुखी रहता है कि पोस्टमास्टर साहब पूरे गांव की चिट्ठियां बांटते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई चिठियाँ नहीं लिखता। गांव के पंडित जी एक अधेड़ और दुहाजू का रिश्ता उनकी बेटी सीमा के लिए लाते हैं, लेकिन वह इंकार कर देते हैं। दूसरी तरफ गांव के स्कूल का मास्टर और लड़कों की टीम बना कर समाजसेवा करने वाला रजत सीमा को चाहता है और सीमा भी उससे प्रेम करती है। सब कुछ अपनी गति से चलता रहता है तभी फिल्म में अचानक एक ऐसा घुमाव आता है कि साधारण से दिखने वाली यह कहानी असाधारण हो जाती है। पोस्टमास्टर साहब को एक चिट्ठी और एक पांच लाख रुपये का चेक आता है। चिट्ठी में यह लिखा होता है कि यह रकम गांव के विकास के लिए खर्च की जाए और साथ ही यह हिदायत भी कि यह चेक गांव के सबसे ईमानदार और अच्छे आदमी के हाथ में सौंपा जाए।

पोस्टमास्टर साहब गांव के सबसे तथाकथित जिम्मेदार आदमियों को इकट्ठा करते हैं और यह समस्या उनके सामने रखते हैं। तय होता है कि अगले महीने एक चुनाव होगा और गांव के लोग वोटिंग के जरिए इन लोगों में से सबसे अच्छे आदमी का चुनाव करेंगे। यहाँ से पूरी कहानी बदल जाती है। गांव का डॉक्टर जो बिना फीस लिए किसी गरीब को सलाह तक नहीं देता था, अचानक मुफ्त में घर-घर जाकर मरीजों को देखने लगता है। गांव का जमींदार किसानों का लगान माफ कर देता है और गांव के पंडित जी धर्म के नाम पर सबको बरगलाने की कोशिशों में लग जाते हैं। डॉक्टर साहब इलाज पर इलाज किए जा रहे हैं। हराधन जमींदार साहब से कहता है 'डॉक्टर साहब को लोग गांव का सबसे अच्छा आदमी बता रहे हैं। कुछ मर्ज हो या न हो, वो तो इलाज किये चले जा रहे हैं। कहते हैं हम तो परोपकार करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता'। डॉक्टर की बढ़ती लोकप्रियता से जमींदार साहब डर जाते हैं कि अब तो चुनाव में डॉक्टर ही जीतेगा। लिहाजा वह गांव वालों का दस हजार रुपये का लगान पूरी तरह माफ कर देते हैं। यह खबर लेकर हराधन जब भंजू बाबू के पास जाता है तो उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है और चुनाव का नतीजा सीधा सीधा उन्हें जमींदार साहब के पक्ष में जाता दिखाई देता है। वह ठेकेदार को आदेश देते हैं कि गांव की सभी सड़कें पक्की कर दी जाएँ और छह की जगह बीस ट्यूबवेल लगवा दिए जाएँ। इन सबके बरक्स पंडित तकार्लंकार शास्त्री के पास सबसे बड़ा हथियार है धर्म और उनके भगवान, जिन्हें वह लालच भी दे रहे हैं कि हे प्रभु, एक बार ये रकम हाथ आ जाए तो तुम्हारा मंदिर सोने से मढ़वा दूँगा। गांव के लोग इस परिवर्तन पर हैरान हैं। जमींदार ने लगान माफ कर दिया है, दूसरी तरफ डॉक्टर लोगों का मुफ्त इलाज कर रहा है। गांव की दुकानों-चौपालों पर यह चर्चा का विषय है और वे इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सतयुग आने वाला है। दूसरे गांव में एक बाबा आए हैं, जो ऐसा ही बताते हैं और गांव वालों के पास उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जब चुनाव का दिन नजदीक आने वाला होता है तब तो कमाल ही हो जाता है। दिन भर खाट पर लेट कर हुक्का पीने वाला जमींदार अब खेतों में जा रहा है और किसानों को मुफ्त में बीज बाँट रहा है। मेले में सबको मुफ्त खाना खिला रहा है। डॉक्टर ने बाकायदा अपने अस्पताल को खैराती अस्पताल में बदल दिया है। मुफ्त में नाच दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी शास्त्री जी अपने धर्म वाले कार्ड की वजह से बाजी मारने में आगे हैं। उनकी जमीन से लक्ष्मी जी निकलने वाली हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा पंडित जी को सपने में दर्शन देकर समय तक बता दिया है। लोग जय-जयकार कर रहे हैं और सभी लोगों की जय-जयकार पंडित तकार्लंकार शास्त्री को वोटों में बदलती साफ दिखाई दे रही है, लेकिन लक्ष्मी जी जमीन फाड़ कर निकली कैसे, यह राज भंजू बाबू को पता चल जाता है और वो आपस में चुनाव पूर्व समझौता कर लेते हैं। चुनाव वाले दिन वह सब कुछ होता है जो हमारे लोकतंत्र की शान सा बन गया है, बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग, वोट तोड़ने की कोशिशें और मारपीट। आखिर में एक नाटकीय घटनाक्रम में यह राज खुलता है कि चेक भेजने वाले सर जेसी रॉय कौन हैं और यह चेक किसे मिलना चाहिए। गांव के सब लोग मिल कर निर्णय लेते हैं कि गांव का जो सबसे ईमानदार आदमी है और चेक उसके हवाले कर दिया जाता है।

TO BE CONTINUED...

BRIEF NEWS

शाहरुख बने नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के संगठन मंत्री

RANCHI : मावीया शाहरुख को नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट संस्था का झारखंड प्रभारी

बनाया गया है। इस संबंध में संस्था के झारखंड के संयोजक अली रजा जैदी ने लेटर जारी किया है। उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि शाहरुख को दी गई जिम्मेदारी को वह ईमानदारी से निभाएंगे और संस्था की साख को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उनकी सफलता की कामना की जाती है।

बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले आरोपी दोषी करार

RANCHI : स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने बैंक अधिकारी बन कर करोड़ों की ठगी करने वाले पांच लोगों को शनिवार को दोष करार दिया।सभी दोषियों की सजा 23 जुलाई को सुनाई जाएगी। स्पेशल कोर्ट के जज पीके शर्मा ने गणेश मंडल, उसके पुत्र प्रदीप मंडल, संतोष मंडल, उसके पुत्र पिंटू मंडल और अंकुश कुमार मंडल को दोषी करार दिया है। चार दोषी जमानत पर थे, जिन्हें कोर्ट के आदेश के बाद हिरासत में ले लिया गया। जबकि एक दोषी अंकुश मंडल पहले से ही देवघर जेल में बंद है। सभी दोषियों पर फर्जी पते पर सिम कार्ड लेने और बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करके साइबर अपराध करने का आरोप सिद्ध हुआ है। ईडी ने इस मामले के ट्रायल के दौरान कुल 24 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किये।

सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार, दूसरा बरी

RANCHI : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी प्रदीप सिंह को पोस्को की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। उसकी सजा के बिंदु पर अदालत 26 जुलाई को सुनवाई करेगी। वहीं साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी नीलू लोहरा को कोर्ट ने बरी कर दिया। दरअसल, दुष्कर्म का यह मामला नामकुम थाना के अंतर्गत खरसीदाग ओपी क्षेत्र का है। आरोप था की 19 जून 2021 को प्रदीप सिंह ने 14 वर्षीय नाबालिग को फोन कर घर से बुलाया था और सुनसान जगह पर ले जाकर अपने साथी नीलू लोहरा के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।पीड़िता घर लौटकर मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी थी । जिसके बाद दूसरे दिन 20 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। नाबालिग पीड़िता और आरोपी नीलू लोहरा एक ही गांव के रहने वाले है। जबकि आरोपी प्रदीप सिंह लापुंग के परसा गांव के रहने वाला है। पीड़िता के गांव में रहकर वह गाड़ी चलाने का काम करता था। पीड़िता और आरोपी एक ही गांव में रहने की वजह से दोनों परिचित थे। मामला सामने आने के बाद इस दुष्कर्म की घटना को दबाने की भी कोशिश की गई थी।गांव में ही पीड़िता के परिजनों पर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी।लेकिन पीड़िता के परिजन नही माने और थाना में जाकर प्रथिमिकी दर्ज कराई थी।

मोरहाबादी मैदान से सीएम आवास का घेराव करने निकले थे आंदोलनकारी

पारा शिक्षकों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, मची भगदड़

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी में सीएम आवास का घेराव करने निकले पारा शिक्षकों का पुलिस से भिड़ंत हो गया। पुलिस ने पारा शिक्षकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। बता दें कि झारखंड के पारा शिक्षक हजारों की संख्या में रांची के मोरहाबादी मैदान से सीएम आवास का घेराव करने निकले थे। दूसरी तरफ पुलिस किसी भी तरह से उन्हें सीएम आवास तक पहुंचने नहीं देने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे में शिक्षकों और पुलिस कर्मियों में टकराव की आशंका पहले से थी। सीएम आवास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने पारा शिक्षकों को रोक दिया, जिसके बाद पारा शिक्षक आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने उनपर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं।

आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस व सीएम आवास का घेराव करने जाते पारा शिक्षक। ● फोटोन न्यूज

पुलिस छावनी में तब्दील हुई राजधानी

सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन के बाद राजधानी में पारा शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान से लेकर सीएम आवास तक के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पारा शिक्षकों के सीएम आवास के घेराव को देखते हुए मोरहाबादी मैदान में पुलिस ने अपना सुरक्षा घेरा तैयार किया है। पूरे मोरहाबादी मैदान की विशेष प्रणाली के तहत घेराबंदी की गई है। 1000 से ज्यादा जवानों को मोरहाबादी मैदान की घेराबंदी में लगाया गया है। रांची के सिटी एसपी सहित कई थानों के थानेदार मोरहाबादी मैदान में कैंप कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि पारा शिक्षक वेतनमान के साथ-साथ अपने आप को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पारा शिक्षकों ने सरकार को मार्च महीने तक इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की बात रखी थी। लेकिन सरकार के स्तर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिसके बाद पारा शिक्षकों ने रांची जाकर सीएम आवास घेराव करने का कार्यक्रम तय कर लिया। पारा शिक्षकों के अन्य मांगों में पीएफ का लाभ, झारखंड में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन जल्द करवाना, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पारा शिक्षक को प्रावधान के अनुरूप अंक में छूट देना और बिहार के तर्ज पर राज्य कर्मी का दर्जा देना शामिल है।

राज्य सरकार से बातचीत कर मुद्दा सुलझाने की अपील

घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने रिम्स पहुंचे हिमंता

रिम्स में घायल सहायक पुलिसकर्मी से बातचीत करते हिमंता। ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI : असम के मुख्यमंत्री और आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार सुबह रिम्स पहुंचकर लाठीचार्ज में घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। हिमंता ने रिम्स में भर्ती सहायक पुलिसकर्मियों से घटना की पूरी जानकारी ली। डॉ सरमा ने राज्य सरकार से बातचीत कर मुद्दा सुलझाने की अपील की है। रांची रिम्स में सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में हिमंता बिस्व सरमा ने कहा कि शुक्रवार को कुछ सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मैं बस इतना चाहता हूं कि राज्य सरकार सहायक पुलिस कर्मियों के साथ बात करे और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय से ही झारखंड में ऐसा माहौल देखा जा रहा है। झारखंड में स्थिति बिगड़ती जा रही है। यहां स्थिति को सुधारने की जरुरत है।

स्थायी करने के लिए हड़ताल के अंतिम दिन जमे रहे मनरेगा कर्मी

मशाल जुलूस निकालते मनरेगा कर्मी। ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का ह्यवादा निभाओ, स्थायी करो मुहिम के तहत तीन दिनों की सांकेतिक हड़ताल के अंतिम दिन तक समूचे राज्य के मनरेगा कर्मी सभी जिला मुख्यालयों में जमे रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, शनिवार शाम को रांची अलबर्ट एक्का चौक में मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस के माध्यम से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई। मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जॉन बागे ने कहा कि सरकार बिल्कुल ही निरंकुश हो गई है। जान बूझ कर मनरेगा कर्मियों को हड़ताल करने पर विवश कर रही है। अपने कार्यकाल में मनरेगा कर्मियों को झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दिया। ग्रामीण विकास मंत्री का आवास घेराव, विधानसभा घेराव, 100 किलो मीटर पद यात्रा, मुख्यमंत्री आवास घेराव सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होने के बावजूद संज्ञान न लेना, सरकार की निरंकुशता को दशार्ता है। मनरेगा कर्मी 17 वर्षों से भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में अपना योगदान दे रहे हैं। पूरी जवानी सरकार की सेवा में दे दिए। अब बुढ़ापे में कहां जाएंगे।

एचडीएफसी बैंक कर्मी की हत्या के मामले में तीन गिरफ्तार, हथियार बरामद

RANCHI : अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू फल मंडी के पास एचडीएफसी बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में दानिश तथा दो अन्य हैं। इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। मामले की पुष्टि एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने की है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार की रात अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित हरमू फल मंडी के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अरगोड़ा निवासी अभिषेक कुमार सिंह के रूप में की गई। वह मेन रोड स्थित एचडीएफसी बैंक के लोन सेक्शन में कार्यरत था। लूटपाट का विरोध करने पर अभिषेक की गोली मारकर हत्या की गई थी।

सीबीआई कोर्ट ने पंकज को कहा- सबूतों व तथ्यों को एफिडेविट के रूप में करें पेश

PHOTON NEWS RANCHI : 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की क्लोजर रिपोर्ट मामले की सुनवाई शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कोर्ट में हुई। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता पंकज यादव और सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा कमेटी के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सीबीआई जांच को जारी रखने की मांग की। पंकज ने राष्ट्रीय खेल मेगा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स निर्माण में अनियमितता समिति की विधानसभा कमेटी के संयोजक सरयू राय तथा सदस्य राधाकृष्ण किशोर के निष्कर्ष और अनुशंसा पर कार्रवाई करने की मांग की। पंकज यादव के वकील प्रशांत कुमार ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा है कि दो विभागों में कम्युनिकेशन गैप के कारण ये अनियमितता हुई है, जो समझ से परे है। पंकज यादव ने कोर्ट के समक्ष परामर्शी का चयन और तत्कालीन खेल मंत्री की ओर से टेंडर खुल जाने के बाद अपने पसंदीदा सवेंदक को टेंडर दिलाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही तत्कालीन मंत्री सुदेश महतो और उनके आप्त सचिव गोपालजी तिवारी का विदेश भ्रमण का मुद्दा भी उठाया। सीबीआई कोर्ट ने इन सारी बातों को तथ्यों के साथ एफिडेविट के रूप में 20 अगस्त तक जमा करने का निर्देश दिया। सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा कमेटी के सदस्यों से पूछे बगैर क्लोजर रिपोर्ट जमा कर देने पर सीबीआई की मंशा पर सवाल उठाया है।

विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 26 को

पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में जमीन घोटाला मामले के आरोपित आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर शनिवार को सुनवाई हुई। मामले में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। कोर्ट ने ईडी को समय देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 26 जुलाई निर्धारित की है। विनोद सिंह ने अदालत में 15 अप्रैल को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में विनोद सिंह का नाम तब आया, जब ईडी से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल से हेमंत सोरेन के साथ व्हाट्सएप चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सिफारिश की लिस्ट और बड़गाई की विवादित जमीन पर बैंक्विट हॉल बनाने के संबंध में डिजाइन मिला था। ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े भूमि घोटाले मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसके बाद से विनोद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 30 मार्च को ईडी के अधिकारियों ने रांची की पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। इस मामले में बड़गाई इलाके के भू- राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

हर दिन पांच महिलाओं के साथ हो रहा दुष्कर्म : बाबूलाल

RANCHI : बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में मां बहनों की

इज्जत सुरक्षित नहीं है। हर दिन पांच महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। हर दिन पांच हत्या और हर दिन पांच दंगे होते हैं। सबसे अधिक दुष्कर्म झारखंड में हुआ है। पुलिस भी नहीं सुन रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। बाबूलाल ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में बिना पैसा के काम नहीं होता। भ्रष्टाचार सरकार द्वारा पेषित हैं। अफसर कहते हैं कि हम पैसा देकर आए हैं, तो पैसा लेंगे ही। पुलिस को वसूली में लगाकर रखा गया है। झारखंड में 13 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कोई बता दे कि इस दौरान जमीन लूट हुई हो। सबसे अधिक जमीन हेमंत सोरेन ने लूटा है।

पहाड़ी मंदिर के पास शिविर लगाएगा हिंदू जागरण मंच

RANCHI : हिंदू जागरण मंच विगत 20 वर्षो से सावन के पावन माह में सावन के हर सोमवारी को पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सेवा शिविर लगाते आया है। इस वर्ष भी मंच सुखदेव नगर मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह के नेतृत्व में निःशुल्क सेवा शिविर लगाने को लेकर अहम बैठक हुई। सावन की हर सोमवारी को सभी भक्तों के लिए दूध पुष्प बेलपत्र आदि का वितरण किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से हिंदू जागरण मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी सुजीत सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक में मुख्य रूप से रांची महानगर अध्यक्ष निशांत चौहान चंदन सिंह, राहुल सिंह राजपूत, कर्ण कर्मकार, अमित चौधरी अभिजीत मिश्रा,अंश कुमार, सूरज कुमार, पृथ्वी राज सिंह, सत्य सिंह, सिम्पी शर्मा, रवि चौधरी, अंकित जेदिया, कुणाल सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रभारी से मिले उर्दू और संस्कृत शिक्षक

PHOTON NEWS RANCHI : शनिवार को झारखंड सरकार के कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रभारी उमैर खान से कांग्रेस भवन में झारखंड मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मौलाना मुस्तफा कासमी की अध्यक्षता में मुलाकात की। उमैर खान को पुष्पगुछ देकर प्रतिनिधिमंडल ने मांगपत्र भी सौंपा। झारखंड राज्य में प्रस्वीकृति प्राप्त 46 मदरसा एवं 36 संस्कृत विद्यालय को बिहार के तर्ज पर वेतन मद में अनुदान देने की मांग

- 46 मदरसा व 36 संस्कृत विद्यालयों को बिहार की तर्ज पर की वेतन देने की मांग

की। मौलाना मुस्तफा कासमी ने कहा कि कांग्रस अल्पसंख्यक प्रभारी उमैर खान ने हमारी मांगों को ऊपर तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में मौलाना मुस्तफा कासमी, हाफिज साजीदुल्लाह, गुंजन, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, बलदेव पांडे, अर्जुन पांडेय, धुधु हजाम, समेत दर्जनों शिक्षक थे।

मारवाड़ी कॉलेज में फिल्म फोटोग्राफी व निर्माण विषय में एडमिशन का अवसर

RANCHI : रांची के मारवाड़ी कॉलेज के डिजिटल फोटोग्राफी और फिल्म निर्माण कोर्स में एडमिशन चल रहा है। यह एक वर्ष का डिप्लोमा ऐड ऑन कोर्स है। इच्छुक व्यक्ति या विद्यार्थी मारवाड़ी कॉलेज के वेब साइट में जाकर डीपीएफएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी, जो दूसरे कॉलेज में किसी अन्य विषय की पढ़ाई कर रहा हो या किसी ऑफिस में काम कर रहा हो, या गृहणी हों या जिनको फोटोग्राफी और फिल्ममेकिंग का शौक हो। जो कायदे से रील या लघु फिल्म बनाना चाहते हों वैसे सभी व्यक्ति इस कोर्स में एडमीशन ले सकते हैं। नामांकन के लिए न्यूनतम अर्हता किसी भी विषय से +2 केवल 45 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना चाहिए।

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग कार्यसमिति की बैठक में कई अहम प्रस्ताव हुए पारित

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले शनिवार को रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी शामिल नहीं हो सके। प्रदेश प्रभारी उमैर खान ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में बूथ लेवल तक राहुल गांधी के विचारों को ले जाया जाएगा। झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी उमैर खान ने कहा कि केंद्र में भाजपा अल्पमत में है। इसलिए उनके नेता हताश,परेशान और विचलित हैं।उन्होंने कहा कि जब उनके नेता राहुल गांधी अपने हाथों में संविधान लेकर निकले तो भाजपा वाले भी संविधान की बात करने लगे।इस दौरान उमैर खान ने कहा कि सियासत में संयम रखना बेहद जरूरी होता है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी ने विस्तारित कार्यसमिति की बैठक के बाद कहा कि भाजपा मुद्दाविहीन बातों को मुद्दा बनाने में लगी है, लेकिन झारखंड की जनता प्रेम और भाईचारे में विश्वास रखने वाली हैं। उमैर खान ने कहा कि चुनाव में अयोध्या में प्रभु राम ने सबक सिखाया है।उन्होंने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है।हमें नफरत खत्म कर प्रेम और भाईचारे का संदेश बढ़ाना है।

बैठक में शामिल कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता। ● फोटोन न्यूज

आलू-प्याज सहित अन्य सब्जियों की औसत कीमत में लगभग 40 प्रतिशत तक की हुई वृद्धि

महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी रांची में सब्जियों की कीमतें दिन पर दिन बढ़ रही है। हरी सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। एक माह में ही सब्जियों की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 80-120 रुपए और प्याज 40 से 45 रुपए किलो मिल रहा है। ज्यादातर हरी सब्जियों की कीमतें 40 रुपए के पार हैं। आलू-प्याज सहित सब्जियों की औसत कीमत 40 प्रतिशत तक महंगी हो गई है। इस समय शहर के बाजारों में एक महीने पहले 20 रुपए किलो बिकने वाला आलू 35 रुपए बिक रहा है। लालपुर में सब्जी बेचने वाले बुंदू के सुभाष ने शनिवार को बताया कि सब्जियां महंगी होने का पहला कारण बारिश ठीक से नहीं होना हैं। कम बारिश से टमाटर और सीजन वाली सब्जियां कम हुई या खराब हो गईं। व्यापारियों का कहना है कि लोकल सब्जियों का उत्पादन आधे से भी कम हो गया है। इससे कीमतें बढ़ गई। क्योंकि बाहर से माल मंगाना पड़ रहा है। बेंगलुरु से टमाटर आ रहा है। ये टमाटर 80- 120 रुपए किलो बिक रही है।नागाबाबा खटाल में सब्जी की दुकान लगाने वाली रेखा देवी ने बताया कि कीमतें बढ़ने के कारण उनकी कमाई घट गई है। क्योंकि सब्जियां कम मात्रा में बिक रही हैं। पहले एक बोरा फूल गोभी रोज बेच देते थे, अभी आधा भी नहीं बिक रहा। झींगी और नेनुआ भी लोग कम खरीद रहे हैं।

क्या कहते हैं लोग : नागाबाबा खटाल के समीप सब्जी खरीद रहे राम सिंह ने बताया एक माह में सब्जी के दाम में काफी वृद्धि हुई है। इससे घर का बजट बिगड़ गया है। जहां 1500 रुपये में एक माह सब्जी आराम से चलता था। वहां अभी 2500 रुपये लग रहा है। लालपुर में सब्जी खरीदते नेहा देवी ने बताया कि सब्जी के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ गया है। पहले से दोगुना दाम में सब्जी मिल रहे है। जहां एक हजार लगता था, वहां अब 2000 रुपया लग रहा है।

ये है प्रति किलो सब्जी के दाम

आलू-35, धनिया पत्ता 200, प्याज 40 से 50, अदरक 200, लहसुन 190, शिमला मिर्च 120, हरा मिर्च 80, बेंगलुरु टमाटर 120, लोकल टमाटर 80, मकई 40, फूलगोभी 60, कच्चा केला 40, पालक 40, परवल 40-60, बोदी 40, गाजर 40, खीर 30- 40, भिंडी 40, कद्दू 30, पत्ता गोभी 40, बैगन 50, करेला 40, नेनुआ 35, झिंगी 40-50 रुपये किलो।

जमीन की हेराफेरी को लेकर हेमंत सरकार जारी करे श्वेत पत्र: अर्जुन मुंडा

RANCHI : पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड में सीएनटी-एसपीटी एक्ट को दरकिनार कर बिचौलियों और दलालों ने लूट-पाट मचाई है। इस पर राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। युवाओं का भविष्ट अंधकार में है। 7000 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी हैं। इसपर राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वे शनिवार को भाजपा की विस्तृत कार्यसमिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

आज से रांची व भागलपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

PHOTON NEWS RANCHI : रांची से भागलपुर के लिए स्पेशल ट्रेन 21 जुलाई से चलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन रांची से रविवार और मंगलवार को चलेगी। वहीं, भागलपुर से सोमवार और बुधवार को रांची के लिए चलेगी। रांची-भागलपुर स्पेशल ट्रेन 21, 23, 28 व 30 जुलाई, 4, 06, 11 व 13 अगस्त को चलेगी। वहीं, भागलपुर-रांची ट्रेन 22, 24, 29 व 31 जुलाई तथा 5, 7, 12 व 14 अगस्त को चलेगी। यह ट्रेन रांची से रात 9.35 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन मुरी से प्रस्थान रात 10.47 बजे, बरकाकाना प्रस्थान रात 12.15 बजे, हजारीबाग प्रस्थान रात 1.20 बजे, कोडरमा प्रस्थान सुबह 2.35 बजे, गया प्रस्थान सुबह 4.30 बजे, तिलैया प्रस्थान सुबह 5.22, नवादा प्रस्थान

सुबह 6.12 बजे, शेखपुरा प्रस्थान बजे सुबह 6.42 बजे, किऊल प्रस्थान सुबह 8.40 बजे व भागलपुर सुबह 10.50 बजे पहुंचेगी। वहीं, भागलपुर से यह ट्रेन दोपहर 12.20 बजे खुलेगी, बांका प्रस्थान दोपहर 2.00 बजे, देवघर प्रस्थान दोपहर 3.15 प्रधानखांटा प्रस्थान शाम 6.20, धनबाद प्रस्थान शाम 6.35, गोमो प्रस्थान शाम 7.07 बजे, हजारीबाग प्रस्थान शाम 7.49 बजे, कोडरमा प्रस्थान रात 8.50 बजे, बरकाकाना - प्रस्थान रात 11.45, मुरी प्रस्थान रात 1.02 बजे व रांची आगमन सुबह 13.00 बजे होगा।

समाचार सार

हाईवे किनारे खड़े 30 वाहनों से वसूला गया जुर्माना

JAMSHEDPUR : उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर शनिवार को डिमना चौक से बालीगुमा और पारडीह के आसपास नेशनल हाईवे के किनारे खड़े 30 वाहनों से जुमार्ना वसूला गया। मोटरयान निरीक्षक सूरज हेम्ब्रम के नेतृत्व में जांच अभियान के दौरान ट्रक, ट्रेलर, हाईवा आदि बड़े वाहनों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस प्रदूषण आदि कागजातों की गहनता से जांच की गई।

जांच के दौरान एक वाहन का टैक्स फेल पाया गया, जबकि कई वाहनों का परमिट, इंश्योरेंस के कागजात फेल मिले। मोटर यान निरीक्षक ने कहा कि अवैध रुप से सड़कों पर खड़े रहने वाले वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। परिवहन विभाग की ओर से निरंतर वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा।

विधायक सरयू राय आज करेंगे रामार्चा पूजा

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय 21 जुलाई को रामार्चा पूजा करेंगे। बारीडीह स्थित विधानसभा कार्यालय के पास वाले मैदान में पूजा की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। वेदी बन कर तैयार है। वेदी को सजाने का काम रात तक चलेगा। यह केला के थम के साथ-साथ तैयार फलों और चांदनी (ढंकने वाला वस्त्र) से तैयार होता है।

22 जुलाई को प्रसाद वितरण के लिए पंडाल का काम तेजी के साथ चल रहा है। रामार्चा पूजा के लिए विशेष तौर पर बेगूसराय से प्रख्यात पुरोहित पं. गौरीकांत ठाकुर आ रहे हैं। मुख्य यजमान सरयू राय रहेंगे।

राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए आवेदन 31 तक : संजय

JAMSHEDPUR : झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अक्टूबर में होगा। अस्मा इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट एवं मित्रा प्रोडक्शन के संयुक्त तत्वावधान में यह महोत्सव होगा। राज्य के स्थानीय भाषा के फिल्मकारों को इस वर्ष से पूर्णतः निशुल्क इंट्री मिलेगी। 31 जुलाई तक इंट्री के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यह जानकारी आयोजक संजय सत्पथी एवं राजू मित्रा ने शनिवार को दी। प्रेस कांफ्रेंस में संजय सत्पथी ने बताया कि इसमे फीचर फिल्म, शार्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो, डॉक्यूमेंट्री जैसे वर्ग में इंट्री जमा की जा सकती है। इसमें शामिल इस बार पांचवे झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में बॉलीवुड एवं झारखंड (झॉलीवुड) के दिग्गज कलाकारों का समागम देखने को मिलेगा। शालिनी प्रसाद ने बताया कि फिल्म के ज्यूरी सदस्य में अनिल रामचंद्र शर्मा, अलीक रॉय, धनंजय मंडल , मानसिंह माझी, राजीव सिन्हा जैसे फिल्म निर्देशक शामिल है। इस दौरान पूर्वी घोष, अरुण बाकरेवाल और शालिनी प्रसाद उपस्थित थी।

मेगा ब्लॉक को लेकर आज 6 ट्रेन रहेंगी रद्द

JAMSHEDPUR : रांची रेलवे डिवीजन में मुरी-बरकाकाना सेक्शन पर रेलवे की ओर से मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इसको लेकर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद करने का फैसला लिया है। रेलवे ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार रविवार को ट्रेन नंबर 08151/08152 टाटा-बरकाकाना-टाटा मेमू पैसेंजर, ट्रेन नंबर 08195/08196 टाटा-हटिया-टाटा मेमू स्पेशल और ट्रेन नंबर 18601/18602 टाटा-हटिया-टाटा एक्सप्रेस रद रहेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 08641/08642 आद्रा-बरकाकाना-आद्रा मेमू पैसेंजर और 18085/18086 खड़गपुर-रांची-खड़गपुर मेमू एक्सप्रेस रविवार को रद रहेगी।

महादेवशाल में आज से 22 अगस्त तक रुकेंगी 18 ट्रेनें

JAMSHEDPUR : दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने सावन महीने में भगवान शिव का दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महादेव शाल स्टेशन पर 18 ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया है। यह सभी ट्रेन रविवार से 22 अगस्त तक दो मिनट का ठहराव दिया गया है। रेलवे के सर्कुलर के मुताबिक दुर्ग -आरा दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, टाटा-इतवारी एक्सप्रेस, टाटा-बिलासपुर एक्सप्रेस, हावड़ा-टिटलागढ़ एक्सप्रेस, हावड़ा-कांटाबाजी एक्सप्रेस, बादामपहाड़-राउरकेला एक्सप्रेस, हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस, टाटा-राउरकेला मेमू, चक्रधरपुर -राउरकेला मेमू अप-डाउन दोनो ओर से 2 मिनट के लिए महादेव शाल स्टेशन पर रूकेगी।

बर्बर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगा झारखंडी समाज : विजय

RANCHI : शनिवार को संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव झारखंड छत्तीसगढ़ प्रभारी विजय शंकर नायक ने पारा शिक्षकों के शांतिपूर्वक ढंग से किए जा रहे आंदोलन पर लाठीचार्ज एवं आंसू गैस के गोला छोड़े जाने पर कहा कि सत्ता में बौराई इंडिया गठबंधन की सरकार की बर्बर कार्रवाई को झारखंडी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार अब यह नहीं चाह रही है कि राज्य में कोई आंदोलन सरकार के खिलाफ हो, जिसका ही परिणाम है कि पहले बर्बरता पूर्वक सहायक पुलिस बल के आंदोलन पर लाठी चार्ज किए गए और फिर पारा शिक्षकों एंव शिक्षिकाओं को निशाना बनाया गया।

ठगी के पैसों से आरोपी ने खोल दिया लाखों का मेगा मार्ट

PHOTON NEWS JAMTARA : साइबर ठगी के जरिए आरोपित ने इतनी रकम इकट्ठी कर ली कि उसने कई संपत्तियां तो बनाई ही मेगा मार्ट समेत कई कारोबार भी खड़े कर लिए। ऐसे ही एक मामले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज साइबर थाने की पुलिस साइबर ठग आरोपितों की तलाश में करमाटांड़ थाना पहुंची। जहां रमजानी मोड़ कुर्बा के सद्दाम अंसारी उर्फ खुशी मेगा मार्ट के मालिक, इसी गांव के मुस्तफा, सरजहान अंसारी और बेलाल राजा की यूपी पुलिस को तलाश है। इस दौरान पुलिस टीम ने आरोपितों के घरों व दुकानों पर नोटिस चिपकाया। यह मार्ट सद्दाम का बताया जा रहा है। प्रयागराज के पुलिस निरीक्षक मोहम्मद आलमगीर ने थाने में सूचना देकर बताया कि इन लोगों के साइबर ठगी के जरिए 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। आरोपितों ने आगरा कलेक्ट्रेट आगरा के किशन लाल जो एसबीआई बैंक के खाताधारक हैं, उनके दो खातों से ये पैसे ट्रांसफर किए हैं।

आगरा कलेक्ट्रेट के कर्मी से 65 लाख की ठगी का है आरोपी, इलाहाबाद पुलिस ने 2022 में दर्ज किया था मामला

बैंक अधिकारी बनकर की ठगी

प्रयागराज पुलिस ने बताया कि किशन लाल के खाता संख्या 204201 46657 में 22 अप्रैल 2023 को 42,17,813 .38 रुपये थे। जिसमें नेट बैंकिंग के साथ एसबीआई क्रेडिट कार्ड की सुविधा थी। 23 अप्रैल 2023 को उनके मोबाइल नंबर 9838796469 पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी बैंक अधिकार बने साइबर ठग के मोबाइल संख्या 9310 305155 से काल आया और इसी फोन धारक द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2023 से क्रेडिट कार्ड से शापिंग व उनके एसबीआई के खाते से पैसों के डेबिट होने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर 30 अप्रैल 2023 को फोन करने को कहा तो उन्होंने अपने इसी नंबर से फोन किया। काल करने पर बताया गया कि उनके पैसे रिफंड नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद भी उनके खाते से पैसे डेबिट होते रहे। दिनांक चार मई 2023 तक उनके इस खाते का कुल रुपया 41 लाख रुपये से अधिक का डेबिट हो चुके थे।

करमाटांड़ के कुर्बा मोड़ के पास आरोपी सद्दाम ने लाखों की लागत से बनाया खुशी मेगा मार्ट

कई संपत्तियों का भी है मालिक

ठगी के पैसों से कई अपराधी बन गए कारोबारी

तकरीबन एक दशक से भी ज्यादा वक्त से ठगी के जरिए कई अपराधियों ने ठगी के जरिए इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि अपनी काली कमाई से कई तरह का बिजनेस और दुकानें खोलकर आराम से जिंदगी गुजार रहे। हालात यह हैं कि क्षेत्र की बड़ी दुकानों के मालिक व बिजनेसमैन इन अपराधियों के सामने कम पूंजी के अभाव में मंदी की मार झेल रहे हैं। खुशी मेगा मार्ट नाम से रमजानी मोड पर जो दुकान है वह क्षेत्र का सबसे बड़ी दुकान है। इसे एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की तर्ज पर बनाया गया है।

ठगों ने पत्नी के साथ खोले गए ज्वाइंट अकाउंट से भी ट्रांसफर कर लिए पैसे

किशन लाल का एक खाता उनकी पत्नी के साथ ज्वाइंट है और प्रयागराज के कालिंदीपुरम एसबीआई ब्रांच का है। इसका खाता संख्या 4091 80 10408 है, इसमें नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन मोबाइल नंबर एक होने की वजह से इस खाते में जमा कुल 24,50,000 रुपये भी इन अपराधियों ने डेबिट कर लिया। 23 अप्रैल 2023 से चार मई 2023 तक उनके दोनों खातों से कुल 65 लाख रुपये की निकासी कर ली गई। इतना ही नहीं उनके क्रेडिट कार्ड 435 8 78644 542232 से भी दो लाख रुपये से अधिक राशि की शापिंग की गई है। खाते से पैसों की निकासी का पता बैंक शाखा कालिंदीपुरम पर जाने पर हुआ। जिसके बाद प्रयागराज साइबर थाने में किशन लाल ने साइबर ठगी का केस दर्ज करवाया।

बदमाशों ने गाड़ा लाल झंडा, एचएम ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार

स्कूल में हथियार के साथ घुसे उपद्रवी, शिक्षकों को दी धमकी

PHOTON NEWS DHANBAD : जिले के पूर्वी टुंडी अंचल क्षेत्र में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोरतोल के चहारदीवारी निर्माण को एक शख्स ने रुकवा दिया है। दरअसल, शख्स ने जमीन पर अपना दावा पेश किया है। शख्स का नाम बाबू राम मांझी है और वह विद्यालय के बगल का रहने वाला है। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक बिनोद हेंब्रम ने सीओ से शिकायत की है। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि बीते दिनों बाबू राम मांझी तीन-चार लोगों के साथ हरवे-हथियार के साथ लैस होकर विद्यालय में घुस आया और भय बनाने की कोशिश की। साथ ही बाबू राम मांझी ने विद्यालय की चहारदीवारी का काम बंद करा दिया और अंजाम भुगतने की धमकी दी। विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि प्रकरण के बाद से स्कूली बच्चे डरे-सहमे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल की चहारदीवारी निर्माण के दौरान बाबूराम मांझी नामक शख्स तीन चार लोगों के साथ हरवे-हथियार के साथ पहुंच गया और स्कूल की जमीन पर अपना दावा किया है। इस दौरान उसने स्कूल की चहारदीवारी निर्माण कार्य को रोक दिया और जमीन पर लाल झंडा गाड़ दिया है। साथ ही चहारदीवारी निर्माण करने पर बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने सीओ से शिकायत की है। सीओ को दिए गए आवेदन ने प्रधानाध्यापक ने उल्लेख किया है कि हथियार के साथ बाबूराम मांझी नामक स्कूल पहुंचा था और धमकी दी है।उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में पूर्वी टुंडी के सीओ देवराज गुप्ता ने कहा कि स्कूल के प्रधानाध्यापक का आवेदन मिला है। स्कूल की जमीन पर एक शख्स दावा कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। स्कूल में हथियार से लैस होकर पहुंचना गलत है। पुलिस को इस संबंध में कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।

उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोरतोल व कैंपस में गाड़ा गया लाल झंडा।

बीएससी नर्सिंग के पहले सेमेस्टर की कॉपियों का हो पुनर्मूल्यांकन

ज्ञापन सौंपते युवा आजसू के सदस्य। ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI : शनिवार को युवा आजसू का एक प्रतिनिधिमंडल विशाल कुमार यादव के नेतृत्व मे रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. आशीष कुमार झा से मुलाकात कर उन्हें छात्र छात्राओं की परेशानी से अवगत कराया। मौके पर मौजूद युवा आजसू के विशाल कुमार यादव ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत बीएससी नर्सिंग सत्र 22झ26 के 19 नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं का सेम 1 का परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा करवाया गया था, जिसमें 60%से जायदा छात्र-छात्रा फेल हो गए। इनके विरोध के बाद विश्वविद्यालय द्वारा सप्लीमेंट्री परीक्षा कराई गई, तो उसमें 80% से ज्यादा छात्र-छात्रा फेल हो गए। फिर छात्र-छात्राओं के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें कहां गया कि आप सभी छात्र छात्राओं के कॉपी का पुनः मूल्यांकन कर रिजल्ट में सुधार किया जाएगा, परंतु 4 महीना बीत जाने के बावजूद ना ही कॉपी का पुनः मूल्यांकन किया गया, और ना ही रिजल्ट में सुधार हुआ।

पिठोरिया के मुहर्रम जुलूस में शामिल हुए कई अखाड़ाधारी

PHOTON NEWS PITHOURIA: सेंट्रल मुहर्रम कमेटी पिठौरिया के तत्वावधान में पिठौरिया क्षेत्र में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जुलूस में पिठोरिया, बालू, बाढ़ू, सेमरटोली, नायाटोली, पिरुटोला, कोनकी, भागलूपुर सहित कई अखाड़ाधारी शामिल हुए। अखाड़ाधारी हाथों में तिरंगा झंडा व इस्लामिक निशान (झंडे) के साथ पारंपरिक लाठी डंडा, तलवार, बरछा लेकर पिठोरिया चौक होते हुए सैकड़ों की संख्या में मुहर्रम मैदान पहुंचे। जुलूस में कई आकर्षक झांकियां देखने को मिला। जबकि जुलूस में शामिल अखाड़ेधारी पिठोरिया चौक और मुहर्रम मैदान में लाठी, भाला, तलवार आदि का हैरतअंगेज करतब दिखाए। जुलूस में कोलकाता के बैंड द्वारा प्रस्तुत ह्यऐ मेरे वतन के लोगोंह्ल सहित कई देशभक्ति धुन प्रस?तुत की गई। मुहर्रम कमेटी के सदर सुभान अंसारी, शहबान अंसारी,

संरक्षक सज्जाद खलीफा, फिरोज आलम, हफीज अंसारी, सईद अंसारी, सरवर खान, आरिफ खलीफा, आसिफ खलीफा, शाहरुख खलीफा, वशिम खलीफा, असगर अली, खुर्शीद, राजा द्वारा सभी अखाडे. के खलीफा, मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी शकील अंसारी, विशिष्ट अतिथि युथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जमील अख्तर, इंस्पेक्टर महेश्वर प्रसाद रंजन, थाना प्रभारी गौतम कुमार रॉय, अनील केशरी, मोख्तार अंसारी, जाकिर अंसारी, महिबुल्लाह अंसारी, मशीउद्दीन अंसारी सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों को पगड़ी पहना और तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया।

फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में नाबालिग धराया

JAMSHEDPUR : जुगसलाई में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। शनिवार को नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में बाल सुधार गृह भेज दिया है। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर कई सारे रील्स देखे थे, जिसे देखकर उसने जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया था। हालांकि इस दौरान उसे कई लोगों ने रोका था, जिसके बाद उसने झंडा लहराना बंद कर दिया था। बता दें कि 16 जुलाई की रात मुहर्रम जुलूस के दौरान जुगसलाई में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले में दंडाधिकारी प्रेम प्रकाश हेंब्रम के बयान पर जुगसलाई थाना में अज्ञात के खिलाफ शांति भंग करने का प्रयास करने और आदेश की अवहेलना करने का मामला दर्ज कराया गया था।

आदिवासी जमीन की लूट-खसौट के खेल के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार : एलएन मुंडा

PHOTON NEWS RANCHI : शनिवार को आदिवासी जमीन बचाओ अभियान के तहत एक संवाददाता सम्मेलन, धूमकुड़िया भवन, करमटोली, रांची में की गई। इसमें आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक, सामुदायिक और निजी सभी तरह की जमीनों की लूट खसौट जबरन दखल-कब्जा, जमीनमाफिया, बिल्डर बिचौलिया दलालों से राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत करके दस्तावेजों में हेराफेरी, राज्य भर पुलिस प्रशासन जमीन माफिया गठजोड़ का दबदबा से परेशान, पीड़ित हजारों लोगों द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्री,अधिकारियों को दिए गए आवेदन के बाद भी कारवाई नही होने से आक्रोशित आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 21 जुलाई को होने वाले महाधरना की जानकारी दी। आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक लक्ष्मीनारायण मुंडा ने कहा कि आदिवासी जमीन की लूट-खसौट के खेल लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। हेमंत सोरेन सरकार

संवाददाता सम्मेलन में शामिल लोग। ● फोटोन न्यूज

भ्रष्ट-अधिकारियों,जमीन माफिया गिरोह का संरक्षक बनी हुई है। पूर्व विधायक देव कुमार धान ने कहा कि राज्य में जमीन माफिया और अंचल अधिकारियों की सांठ-गांठ से आदिवासी जमीन की हेराफेरी, छेड़छाड़ की जा रही है। सरना सदान मूलवासी मंच के अध्यक्ष सूरज टोप्पो ने कहा कि कल 21 जुलाई 2024 के धरना कार्यक्रम के बाद से राज्य भर में आदिवासी जमीन की लूट-खसौट के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। काके रोड सरना समिति के अध्यक्ष डब्लू मुंडा ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासियों को लूटा जा रहा है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्ट-अधिकारियों की संरक्षक बनी हुई है। संवाददाता सम्मेलन को आदिवासी महासभा के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक देवकुमार धान, अध्यक्ष लक्ष्मीनारायन मुण्डा, आदिवासी मुलवासी सदन मंच के अध्यक्ष सूरज टोप्पो,काके रोड सरना समिति के अध्यक्ष डब्लू मुण्डा, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा एवं जगलाल पहान, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फुलचंद तिर्की तथा अभय भूटकुवर, मोहन तिर्की, निर्मल पहान, तानसेन गाड़ी, टिंकल पहान आदि मौजूद थे।

फोटोन न्यूज फॉलोअप वित्त पदाधिकारी के रूप में कार्यकाल खत्म होने के बाद नाम की अनुशंसा कर फिर दिलाया गया एक्सटेंशन

वीमेंस यूनिवर्सिटी में दो लोग मिलकर ले रहे खरीद-बिक्री के फैसले

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ. अंजिला गुप्ता की ओर से गठित की गई परचेज एंड सेल्स कमेटी सवालों के घेरे में आ गई है। विश्वविद्यालय की ओर से दी जा रही आधिकारिक सूचना के अनुसार यूनिवर्सिटी के परचेज एंड सेल्स कमेटी में कुल तीन लोग हैं, जिसमें दो पदों की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के पास है। यानी कमेटी में कुल तीन लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में महज दो लोग मिलकर खरीद-बिक्री से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किए गए हैं। डॉ. जावेद अहमद डीन साइंस तथा बतौर वित्त अधिकारी मेंबर सेक्रेटरी के रूप में कमेटी में शामिल किए गए हैं।

पांच सबर छात्राओं का निःशुल्क एडमिशन

जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी में 5 सबर छात्राओं का निशुल्क एडमिशन किया गया है। इनका परीक्षा शुल्क भी माफ कर दिया गया है। इन सभी छात्राओं ने स्नातक प्रथम वर्ष के इतिहास ऑनर्स में दाखिला लिया है। इनके रहने के लिए छात्रावास में व्यवस्था की गई है।

जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी पहुंचे लोजपा नेता, कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

सिदगोड़ा स्थित जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रा के बेहोश होने के मामले में बरती गई लापरवाही का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर लोजपा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं होने पर अपनी आपत्ति जताई है। पार्टी के प्रदेश महासचिव बंटी उपाध्याय ने शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलसचिव राजेंद्र जायसवाल एवं डॉ सुधीर कुमार साहू से मिलकर विगत गुरुवार को यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर छात्रा के बेसुध होने पर सुरक्षा कर्मियों की कार्यप्रणाली से लेकर ठेकेदार के सुपरवाइजर एवं सुरक्षा कर्मियों के पत्रकार से उलझने तक की घटना की निंदा की। साथ ही दोबारा ऐसा होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बंटी उपाध्याय ने बताया कि यूनिवर्सिटी परिसर में प्राथमिक उपचार केंद्र के सवाल पर कुलसचिव ने जल्द से जल्द या सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस दौरान पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

आखिर डॉ. जावेद अहमद पर इतनी मेहरबानी क्यों : विश्वविद्यालय की वर्तमान व्यवस्था में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर डॉ. जावेद अहमद पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। डॉ. पीके पाणि का कार्यकाल खत्म होने के बाद से डॉ. जावेद अहमद लगातार विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी बने हुए हैं। कार्यकाल खत्म होने के बावजूद उनका बार-बार एक्सटेंशन कराया जा रहा है। जुलाई में भी बतौर वित्त पदाधिकारी उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन राजभवन को भेजी गई वित्त पदाधिकारी के लिए नाम की अनुशंसा में एक बार फिर डॉ. जावेद अहमद का नाम जोड़ा गया। यह महज संयोग कहा जाए या कुछ और, अनुशंसा में शामिल दो और नाम को किनारे कर एक बार फिर डॉ. जावेद अहमद के नाम पर मुहर लगाई गई।

कौन हैं जावेद अहमद : वित्त पदाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉ. जावेद अहमद गणित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। विश्वविद्यालय में लिए जा रहे वित्त संबंधी तमाम निर्णयों में वह शामिल हैं। वह जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज के समय से ही पदस्थापित हैं।

रजिस्ट्रार और वित्त पदाधिकारी ने नहीं रिसीव किया फोन : पूरे मामले में विश्वविद्यालय का पक्ष लेने के लिए कुलसचिव राजेंद्र जायसवाल और वित्त पदाधिकारी जावेद अहमद से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों ने फोन रिसीव नहीं किया।

विवि में जो कुछ चल रहा, सब बाहर आएगा : छात्र नेता

जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी में चल रहे ठेका सिंडिकेट को लेकर छात्र आजसू के नेता हेमंत पाठक के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय में वित्त समिति की बजाय परचेज एवं सेल्स कमेटी तमाम वित्तीय निर्णय ले रही है। इस कमेटी में केवल दो लोग मिलकर फैसला ले रहे हैं। यह अपने आप में बड़े सवाल पैदा करता है। कमेटी में दो पद पर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। आखिर जावेद अहमद पर इतनी मेहरबानी बनाकर क्यों रखी गई है। इस मामले में राजभवन से शिकायत की जाएगी। जांच में सब कुछ बाहर आ जाएगा।

मानगो पुल पर महाजाम घंटों फंसे रहे हजारों लोग

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : शहर के मानगो पुल के पास शनिवार को घंटों लोग जाम में फंसे रहे। इसका का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि डिमना रोड स्थित ब्लूवेल्स स्कूल से लेकर साकची पंप हाउस गोल चक्कर तक के करीब दो किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। इसका सिलसिला सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और शाम तक यह स्थिति बनी रही। बीच बीच में कुछ मिनट के लिए जरू जाम हटा लेकिन 10 से 15 मिनट में फिर जाम लग जा रहा था।

एम्बुलेंस भी फंसी : मानगो पुल जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसे नजर आए। जिसे पुलिस वाले निकालने के लिए मशक्कत करते दिखे। वहीं बीच- बीच में हुई हल्की बारिश ने भी लोगों को परेशान किया।

यह है जाम की मुख्य वजहः शनिवार को शहर में लगे महाजाम की मुख्य वजह मानगो में नए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य है। क्योंकि इसके पाइलिंग का काम चल रहा। इस दौरान मानगो पुराने ब्रिज के पास दो जगह सड़क को खोद कर गड्ढा बनाया गया है। इससे साकची से मानगो की तरफ जाने वाली आधी सड़क अवरुद्ध हो गई है। यही वजह है कि आज अन्य दिनों के मुकाबले अधिक जाम देखने को मिला। यह स्थिति आगे भी बनी रहेगी।

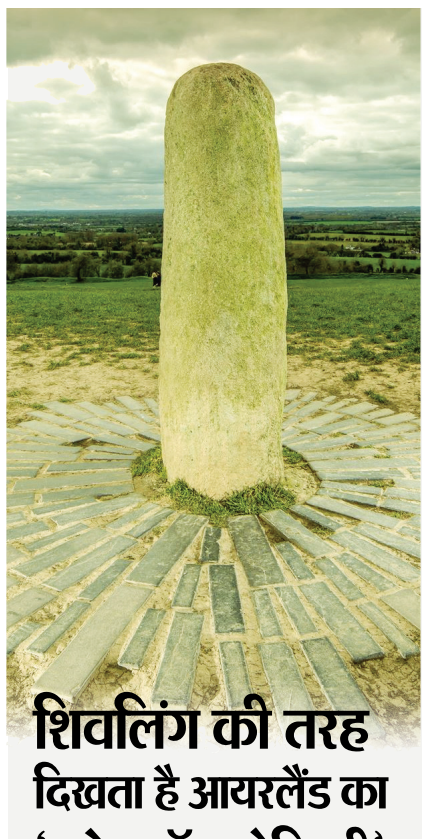

शिवलिंग की तरह दिखता है आयरलैंड का 'स्टोन ऑफ डेस्टिनी'

आयरलैंड में एक खास पत्थर है जिसे लोग कई बार शिवलिंग समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब इसके चर्चे थे, लेकिन वास्तव में यह खास आकार का शिवलिंग नहीं, बल्कि आयरलैंड का 'स्टोन ऑफ डेस्टिनी' है। इसे बोलने वाला पत्थर भी कहा जाता है। यह लिआ फेइल पत्थर आयरलैंड के काउंटी मीथ में तारा पहाड़ी पर स्थित है। वास्तव में यह वहां के राजाओं के लिए राज्याभिषेक पत्थर के रूप में पहचाना जाता है। इसकी ऊंचाई तीन फीट तीन इंच है। इस पत्थर को लेकर मान्यताएं है कि जब आयरलैंड के राजा ने इस पर पैर रखा था, तो खुशी से यह पत्थर दहाड़ने लगा था।

बेहद खूबसूरत है नीदरलैंड का 36 मीटर ऊंचा पिरामिड, अनूठी है ज्यामिति आकृति

नीदरलैंड का ये पिरामिड अपनी अनोखी संरचना के लिए जाना जाता है। इसकी ज्यामिती आकृति बेहद खूबसूरत है। इस पिरामिड को साल 1804 में तैयार किया गया था। इस पिरामिड को फ्रेंच जनरल ने तैयार कराया था। यह फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्ट की सेना का हिस्सा रहा है। यह पिरामिड मिस्त्र में गीजा के पिरामिड से प्रभावित है। इस पिरामिड की ऊंचाई 36 मीटर है, जो कि अब नीदरलैंड की राष्ट्रीय धरोहर बन गया है।

अगस्त में शुरू होगा बर्निंग मैन फेस्टिवल

बेहद अनोखा है रेगिस्तान में इसके जश्न का तरीका

दुनियाभर में कई तरह के फेस्टिवल होते हैं. जो अपने आप में खास होते हैं. इनकी खासियत ही इन्हें एक दूसरे से हटकर बनाती है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे फेस्टिवल के बारे में सुना है जिसमें लोग पूरा शहर ही जलाकर राख कर देते हैं. हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा करने पर लोगों को बधाई भी दी जाती है और उनकी तारीफ की जाती है. ये पूरा फेस्टिवल रेगिस्तान में आयोजित किया जाता है, जहां सबकुछ जलने के बाद रेत पर राख का सिर्फ काला रंग ही पसरा होता है. ये अनोखा फेस्टिवल अमेरिका के नेवादा प्रांत में स्थित ब्लैक रॉक डेजर्ट में आयोजित किया जाता है.

बड़ी मेहनत से जी-जान लगाकर, अपना समय देकर, अपनी रचनात्मकता का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आपने कोई चीज तैयार की हो, तो आप उसे कितना सहेज कर रखेंगे ना! लेकिन क्या आप अपनी ही उस खूबसूरत कलाकृति को खुद आग लगाने की हिम्मत कर सकते हैं। नहीं ना, लेकिन अपनी कलाकृति को आग लगाने का एक फेस्टिवल अमेरिका के नेवादा प्रांत स्थित ब्लैक रॉक डेजर्ट में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को बर्निंग मैन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में होने वाला यह अनोखा फेस्टिवल अगस्त के आखिरी रविवार से शुरू होता है और सितंबर के पहले सोमवार तक चलता है। इसमें लोग खुद कई तरह की कला से जुड़ी चीज़ें तैयार करते हैं। एक तरह से अपना एक शहर बसाते हैं। नाच-गाना होता है और इन कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगती है। लेकिन फेस्टिवल के आखिरी दिन खुद की बनाई कलाकृतियों को वे खुद जला देते हैं। यह काम आसान नहीं है लेकिन इस फेस्टिवल की फिलॉसफी ही यही है कि खुद की रचना को जलाने से अहंकार भी राख हो जाता है। 1986 में सेन फ्रांसिस्को के बेकर बीच पर पहली बार ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था और आज तक इसका आयोजन हो रहा है। कला और संगीत के इस आयोजन में दस हजार से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं।

दुनियाभर में कई तरह के फेस्टिवल होते हैं. जो अपने आप में खास होते हैं. इनकी खासियत ही इन्हें एक दूसरे से हटकर बनाती है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे फेस्टिवल के बारे में सुना है जिसमें लोग पूरा शहर ही जलाकर राख कर देते हैं. हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा करने पर लोगों को बधाई भी दी जाती है और उनकी तारीफ की जाती है. ये पूरा फेस्टिवल रेगिस्तान में आयोजित किया जाता है, जहां सबकुछ जलने के बाद रेत पर राख का सिर्फ काला रंग ही पसरा होता है. ये अनोखा फेस्टिवल अमेरिका के नेवादा प्रांत में स्थित ब्लैक रॉक डेजर्ट में आयोजित किया जाता है. इस फेस्टिवल का नाम बर्निंग मैन फेस्टिवल है, जिसमें हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं. इस बार इसमें करीब 70 हजार लोगों ने शिरकत ली. यहां आने वाले लोग अपने हिसाब से पहले शहर बनाते हैं और फिर फेस्टिवल के अंत में वो खुद अपने हाथों ही सबकुछ जला देते हैं.

साल 1986 से शुरू किए गए इस फेस्टिवल में पहली बार सिर्फ 80 लोग ही आए थे. लेकिन बाद में ये इतना पॉपुलर हुआ कि हर साल ये संख्या बढ़ती ही गई. यहां पर लोग आते हैं और खुद का शहर बसाते हैं. वो कई कलात्मक वाहन और दूसरी कला से जुड़ी चीजें बनाते हैं. इस दौरान नाचना-गाना भी होता है और कला की प्रदर्शनी भी होती है.

फेस्टिवल के आखिरी दिन ये लोग खुद की बनाई कला को जला देते हैं. ऐसा वो यहां की फिलॉस्फी के कारण करते हैं, जिसमें माना जाता है कि खुद ही अपनी रचना को जलाकर अहं भी राख हो जाता है. यहां लोगों को अपने तरीके से जीने की आजादी दी जाती है. उन पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाती है, ताकि वो सही मायने में आजादी का मतलब समझ सकें.

इस फेस्टिवल का सिर्फ एक नियम भी है, जो कम हैरान करने वाला नहीं है. यहां पर ऐसी किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो पर्यावरण को नुकसाना पहुंचाए. इस नियम के कारण ही यहां पर प्लास्टिक के सामान से लेकर फ्यूल वाहन तक बैन हैं. आप यहां पर सिर्फ साइकिल या पैदल ही घूम सकते हैं.

एक व्यक्ति पर होता है 65000 रुपए का खर्च

फेस्टिवल में कला और संगीत को जगह दी गई है। हर कोई वह काम करता है, जो उसका फेवरेट होता है। अमेरिका में हर साल होने वाले इस त्योहार में हजारों लोग शामिल होते हैं और कई चीजों से अलग-अलग आकृतियां बनाकर दुनिया को दिखाते हैं। यह जरूरी नहीं कि यह आकृतियां आकर्षक हो इसलिए ज्यादातर आकृतियां अजीब ही होती हैं। इतना ही नहीं इस फेस्टिवल में लोग अलग और अजीब वेशभूषा भी धारण करते हैं। इस फेस्टिवल में कोई नियम नहीं है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इस त्योहार को संस्कृति में लेने देने वाला पर्व भी कहते हैं। यहां पर खुले मैदान में दूर से दिखने वाली आकर्षक आकृति लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे अंतिम दिन जला दिया जाता है। इस तरह पर्व समाप्त हो जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फायर भी कहते हैं।

फेस्टिवल के लिए अस्थायी तौर पर ब्लैक रॉक सिटी बनती है। 25 हजार रुपए का टिकट खरीदकर उसके सदस्य बनते हैं। पिछले साल 65 हजार लोग वहां पहुंचे थे। एक व्यक्ति का खर्च तकरीबन 65 हजार रुपए होता है। तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में हजारों लोग अपनी धुन में मग्न रहते हैं। हजारों लोग रेगिस्तान में नाचने, गाने और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं।

तीन दोस्तों ने की थी शुरुआत

द बर्निंग मैन फेस्टिवल की शुरुआत साल 1986 में कलाकार लैरी हार्वे ने मित्र जॉन ला और जैरी जेम्स के साथ सैन फ्रांसिस्को के बेकर तट पर की थी। उस समय 9 फीट ऊंचा लकड़ी का पुतला जलाया गया था और तभी से पुतले जलाने की परंपरा है। इस समय यह फेस्टिवल अमेरिका के अलावा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, स्वीडन, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया और कनाडा में भी मनाया जाता है।

कहाँ है ब्लैक रॉक रेगिस्तान

यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (यूएसए) के नेवादा राज्य में स्थित .ब्लैक रॉक डेजर्ट. एक अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र है। -21 जून 1986 से इस रेगिस्तान में बर्निंग मैन-फैस्टिवल मनाया जाता है। यहां दुनियाभर से आए लोग सेलफोन, इंटरनेट, जैसी अत्याधुनिक सुख-सुविधाओं से दूर रहकर पारम्परिक नाच-गाने और गीत संगीत के बीच एक सप्ताह गुजारते हैं।

दुनिया के सबसे बड़ा चूहा कैपीबारा

कैपीबारा एक जिज्ञासु जानवर है। हालाँकि वे आपकी आम सड़क या रसोई की अलमारी में रहने वाले जानवर की तरह नहीं दिखते, लेकिन दक्षिण अमेरिका के ये मूल निवासी दुनिया के सबसे बड़े कृंतक हैं। भले ही वे विचित्र दिखते हों, कैपीबारा जल्दी ही इंटरनेट के छद्म सितारे बन गए हैं - मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि वे बड़े गिनी पिग की तरह दिखते हैं। कैवी परिवार (कैविडे) से संबंधित, उनके सबसे करीबी रिश्तेदार वास्तव में गिनी पिग और रॉक कैवी हैं।

कैपीबारा को हमेशा जल निकायों के पास पाया जा सकता है, क्योंकि उनकी अर्ध-जलीय जीवनशैली होती है। अमेज़ॅन नदी के किनारे, ये गंदे पानी कैपीबारा के लिए कई खतरे पैदा करते हैं, लेकिन पानी के किनारे जीवन अभी भी शिविर लगाने के लिए एकदम सही जगह है - जिससे उन्हें जल्दी से पीछे हटने और एनाकोंडा, जंगली बिल्लियों और यहां तक कि चील जैसे शिकारियों से बचने का मौका मिलता है। जालदार पैर उन्हें पानी में चलने में मदद करते हैं, और उनके चेहरे की विशेषताएं उनके बड़े सिर के ऊपर की ओर स्थित होती हैं, जिससे उन्हें तैरते समय देखने और सांस लेने में मदद मिलती है।

वे पानी में भी सो सकते हैं

कैपीबारा एक बार में 5 मिनट तक गोता लगा सकते हैं और पानी के अंदर रह सकते हैं - अक्सर पानी में सो जाते हैं और अपनी नाक किनारे पर रखते हैं। नदियों, मैंग्रोव और दलदलों के किनारे झपकी लेने से उन्हें ठंडा रहने में मदद मिलती है।

ज़मीन पर भी बेहद फुर्तीले होते हैं

हालांकि कैपीबारा को पानी के किनारे घर जैसा महसूस होता है, लेकिन वे निश्चित रूप से जमीन पर अपना रास्ता जानते हैं, और 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने में सक्षम हैं - जो घोड़े के बराबर है!

उनके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं

कठोर जलीय पौधों और घासों को खाने से होने वाले लगातार घिसाव की भरपाई के लिए उनके मोती जैसे सफ़ेद दांत बढ़ते रहते हैं! खरगोशों की तरह, उनके ऊँचे मुकुट वाले, संकरे किनारे वाले दाँत उनके भोजन को काटने के लिए पूरी तरह से अनुकूल होते हैं। अक्सर प्रकृति के ओटोमन या चलती कुर्सियों के रूप में संदर्भित, ये दोस्ताना जीव कभी भी किसी अन्य जानवर से सवारी साझा करने के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करते हैं। पक्षियों की कई प्रजातियाँ, बंदर, खरगोश और यहाँ तक कि अन्य कैपीबारा को एक बहुत ही विनम्र कैपीबारा की पीठ पर बैठे, बैठे या लेटे हुए देखा गया है।

वे अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं

मिलनसार कैपीबारा लगभग 10-20 के बड़े झुंडों के बीच रहना पसंद करता है, और अक्सर अन्य जानवरों के साथ घुलमिल कर देखा जाता है। 8 ये उदाहरण अक्सर सहजीवी संबंध के प्रदर्शन होते हैं, जिसके तहत एक जानवर, जैसे कि एक पक्षी, कीड़ों के एक मुफ़्त स्मोर्गसबॉर्ड का आनंद ले सकता है, जबकि कैपीबारा आराम से बैठकर अपने मुफ़्त संवारने के सत्र का आनंद लेता है। उनका अविश्वसनीय रूप से सामाजिक स्वभाव उन्हें शिकारियों से बचाने और संभोग की संभावनाओं को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

कैपीबारा शाकाहारी होते हैं

ये शाकाहारी जलीय पौधे, घास, छाल, कंद और गन्ना खाते हैं। और यद्यपि वे जन्म के एक ही सप्ताह में अपनी हरी सब्जियाँ खाने में सक्षम होते हैं, वे अपने जीवन के पहले 16 सप्ताह तक दूध पीते हैं - समूह में किसी भी माँ से बिना किसी भेदभाव के दूध पीते हैं।

वयस्क मनुष्य के बराबर होता है वजन

लगभग 50 किलोग्राम के औसत वजन के साथ, ये बैरल के आकार के स्तनधारी निश्चित रूप से कोई फील्ड चूहे नहीं हैं - इनका वजन 35 से 70 किलोग्राम के बीच होता है। हालाँकि मादा कैपीबारा अपने नर समकक्षों की तुलना में थोड़ी भारी होती हैं।

निजीकरण के इस युग में आज भी सरकारी बैंक क्यों हैं जरूरी

निजीकरण के इस युग में आज भी सरकारी बैंकों का अस्तित्व प्रासंगिक बना हुआ है। 19 जुलाई, 1969 को तत्कालीन सरकार ने देश के 14 प्रमुख बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था। साल 1969 के बाद 1980 में पुनः 6 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए। 19 जुलाई 2024 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 55 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आर्थिक तौर पर सरकार को लग रहा था कि प्राइवेट बैंक देश के सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में सहायक नहीं हो रहे थे। उस समय देश के 14 बड़े बैंकों के पास देश की लगभग 80 फीसदी पूंजी थी। इनमें जमा पैसा उन्हीं सेक्टरों में निवेश किया जा रहा था, जहां लाभ के ज्यादा अवसर थे। वहीं सरकार की मंशा कृषि, लघु उद्योग और निर्यात में निवेश करने की थी। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 1955 तक 360 छोटे-मोटे बैंक डूब गए थे जिनमें लोगों का जमा करोड़ों रुपया डूब गया था। 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद से आज तक भी कई प्राइवेट बैंक डूबने की स्थिति में आए जिन्हें सरकारी बैंकों द्वारा ही संभाला गया। यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक का ताजा उदाहरण हमारे सामने है । लेकिन आज तक कोई सरकारी बैंक नहीं डूबा, क्योंकि इन पर सरकार और रिजर्व बैंक का पूरा नियंत्रण है। 2023-24 में इन्हीं सरकारी बैंकों ने 1.41 लाख करोड़ का लाभ कमाया है और अभी तक चार बैंकों ने 6481 करोड़ लाभांश के रूप में सरकार को दिया है । सरकारी बैंकों को गांवों तक पहुंचने के मकसद से 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। आज देश में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 26 राज्यों और 3 केन्द्रीय शासित प्रदेशों में लगभग 22000 शाखाएं हैं। 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में छह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके विपरीत 1991 के आर्थिक सुधार के बाद सरकार बैंकों के निजीकरण की ओर आगे बढ़ी , जिसे 'नई आर्थिक नीति या एलपीजी नीति' के रूप में भी जाना जाता है। 1994 में नए प्राइवेट बैंकों का युग प्रारम्भ हुआ । आज देश में 8 न्यू प्राइवेट जनरेशन बैंक और 13 ओल्ड प्राइवेट जनरेशन बैंक कुल मिलकर 21 प्राइवेट बैंक काम कर रहे हैं। 2018 में सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की जिसका उद्देश्य पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क का इस्तेमाल करके बैंकिंग को गांव-गांव तक पहुंचाना था । इसके साथ-साथ और कई प्राइवेट पेमेंट बैंकों की भी शुरूआत हुई । 55 वर्षों के कार्यकाल में सरकारी बैंकों ने बैंकिंग को आम जनता तक पहुंचाने का काम तेजी से किया है। जो बैंक आम जनता तक नहीं पहुंच पाए थे, सरकारी बैंकों के सहयोग से लगभग 51 करोड़ जनधन खाते खुलवाकर आम जनता को बैंकों से जोड़ा है। पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार की योजनाओं जैसे जनधन खाते खोलना, मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना, किसान सम्मान की किश्त देने का काम, किसान क्रेडिट कार्ड का क्रियान्वयन इन सरकारी बैंकों ने उत्साह से किया है। प्राइवेट बैंक का इसमें योगदान न के बराबर रहा है । 2008 में एसोसिएट बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय शुरू हुआ जिससे 2017 तक सभी 7 एसोसिएट बैंकों का अस्तित्व समाप्त हो गया । 2019 में सरकारी बैंकों की विलय प्रक्रिया शुरू हुई और 2020 आते-आते 8 बैंकों का अस्तित्व समाप्त हो गया और सरकारी क्षेत्र में 12 बैंक रह गए । सरकार का कहना है की आज के समय में छोटे-छोटे बैंकों की आवश्यकता नहीं है बल्कि 6 से 7 बड़े बैंकों की आवश्यकता है । लेकिन सरकार का यह तथ्य सही नहीं है क्योंकि 2008 में विश्व में बैंकिंग में संकट के समय बड़े- बड़े बैंक भी ध्वस्त हो गए थे । सरकार के केन्द्रीय बजट 2021-22 में वित्तमंत्री द्वारा बताए गए विनिवेश के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के लिए विधेयक पेश किया गया था । निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार इन कानूनों के प्रावधानों को बदलना चाहती है । लेकिन निजीकरण के कारण होने वाले दुष्परिणामों को भी नहीं भूलना चाहिए। निजीकरण से राष्ट्रीयकरण के पहले का दौर फिर से आ सकता है, क्योंकि निजी बैंक एक विशेष वर्ग की जरूरतें पूरी करने में लग जायेंगे ओर आम जनता के लिए बैंकिंग की सुविधाएं महंगी और उनके पहुंच से बाहर हो सकती हैं। देश में चाहे नोटबंदी का समय हो या कोविड-19 की प्राकृतिक आपदा, सरकारी बैंकों ने इन विकट परिस्थितियों में भी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में अपना रोल बखूबी निभाया है। ऐसे में यदि सरकार 55 वर्षों के बाद इन बैंकों के साथ बार-बार नए-नए प्रयोग करके यदि फिर से निजीकरण की ओर बढ़ती है तो अच्छा नहीं होगा। इसकी जगह सरकार को इन सरकारी बैंकों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि निजीकरण से बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है, शाखाएं बंद होंगी और वित्तीय सहायता देने जैसी गतिविधियां प्रभावित होंगी। निजीकरण से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर कम होंगे क्योंकि निजी क्षेत्र कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नीतियों का पालन नहीं करता है। निजी क्षेत्र के बैंक अधिक संपन्न वर्गों और महानगरीय व शहरी क्षेत्रों की आबादी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। इसलिए सरकार को इन बैंकों के निजीकरण के फैसले पर रोक लगानी चाहिए ओर इसकी जगह इन सरकारी बैंकों को और मजबूत करना चाहिए, ताकि ये बैंक देश को विकसित भारत बनाने और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में अपना योगदान कर सकें ।

बेहतरीन रहे जीएसटी के सात वर्ष

ANALYSIS

✍ देवी प्रसाद मिश्रा

जीएसटी के विषय से जुड़े कई दृष्टिकोणों में से एक है- जीएसटी के राजस्व प्रदर्शन पर हाल में हुई चर्चा. जो अन्य बातों के साथ-साथ यह दशार्ती है कि सकल राजस्व संग्रह में तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन इस वृद्धि के अनुरूप शुद्ध राजस्व नहीं बढ़ा है। शुद्ध संग्रह में इस गिरावट को कुछ चिंता के साथ देखा जा रहा है। इसके अलावा, विशेष रूप से धन वापसी (रिफंड) के साथ डेटा की उपलब्धता की कमी तथा जीएसटी परिषद के कामकाज पर भी कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। आइए राजस्व प्रदर्शन से शुरू करते हुए इनमें से प्रत्येक बिंदु पर गहराई से विचार करें। खुशी की बात है कि शुद्ध राजस्व संग्रह लगातार बढ़ रहा है और जीएसटी लागू होने के बाद इसकी वृद्धि की गति बढ़ी है। दूसरा, जीएसटी शुरू होने के बाद की अवधि में शुद्ध राजस्व की वर्ष-दर-वर्ष आधार पर होने वाली वृद्धि (जीएसटी के शुरू होने से पहले की अवधि में 11.81 प्रतिशत की तुलना में) औसतन 12.76 प्रतिशत रही। यह उपलब्धि महामारी के बाहरी झटके के बावजूद है। तीसरा, हम यह देख सकते हैं कि शुद्ध राजस्व वृद्धि ने लगातार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। यह नई कर व्यवस्था की प्रणालीगत दक्षताओं को दशार्ता है। राजस्व संग्रह कर दरों का एक फलन होता है।

सात एक विशेष संख्या है। चाहे गणित (अभाज्य संख्याएं और संख्या सिद्धांत), संगीत (सात संगीतमय स्वर), खगोल विज्ञान (चंद्र चरण में दिन) या पौराणिक कथा (सप्त चक्र, सप्त समुद्र या सप्त ऋषि) हो, सात का चक्र हमारे चारों ओर निरंतर मौजूद है। इसलिए यह प्रयास उचित है कि इस महीने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सात साल पूरे होने पर, हम इस बात की जांच करने के लिए कुछ समय निकालें कि स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़े कर सुधार, जीएसटी, जिसे 1 जुलाई, 2017 की मध्य-रात्रि को लागू किया गया था, का प्रदर्शन कैसा रहा है। तब से, जीएसटी ने बड़े पैमाने पर अकादमिक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अनुपालन के सरलीकरण, लॉजिस्टिक्स में सुधार से लेकर मजबूत राजस्व संग्रह तक के प्रत्येक आयाम की विस्तार से जांच की गई है। जीएसटी के विषय से जुड़े कई दृष्टिकोणों में से एक है- जीएसटी के राजस्व प्रदर्शन पर हाल में हुई चर्चा. जो अन्य बातों के साथ-साथ यह दशार्ती है कि सकल राजस्व संग्रह में तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन इस वृद्धि के अनुरूप शुद्ध राजस्व नहीं बढ़ा है। शुद्ध राजस्व हाल ही में जीएसटी-पूर्व स्तरों पर पहुंच पाया है। शुद्ध संग्रह में इस गिरावट को कुछ चिंता के साथ देखा जा रहा है। इसके अलावा, विशेष रूप से धन वापसी (रिफंड) के साथ डेटा की उपलब्धता की कमी तथा जीएसटी परिषद के कामकाज पर भी कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। आइए राजस्व प्रदर्शन से शुरू करते हुए इनमें से प्रत्येक बिंदु पर गहराई से विचार करें। खुशी की बात है कि शुद्ध राजस्व संग्रह लगातार बढ़ रहा है और जीएसटी लागू होने के बाद इसकी वृद्धि की गति बढ़ी है। दूसरा, जीएसटी शुरू होने के बाद की अवधि में शुद्ध राजस्व की वर्ष-दर-वर्ष आधार पर होने वाली वृद्धि (जीएसटी के शुरू होने से पहले की अवधि में 11.81 प्रतिशत की तुलना में) औसतन 12.76 प्रतिशत रही। यह उपलब्धि महामारी के बाहरी झटके के बावजूद है। तीसरा, हम यह देख सकते हैं कि शुद्ध राजस्व वृद्धि ने लगातार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। यह नई कर व्यवस्था की प्रणालीगत दक्षताओं को दशार्ता है। राजस्व संग्रह कर दरों का एक फलन होता है। यहां संदर्भ के लिए, हम इस तथ्य को याद कर सकते हैं कि कर संग्रह संबंधी दक्षता में सुधार के साथ-साथ कर दरों में उल्लेखनीय कमी आई थी। जीएसटी की शुरूआत से पहले, जीएसटी के लिए राजस्व निरपेक्ष दर (आरएनआर) से संबंधित समिति ने 15-15.5 प्रतिशत की दर की सिफारिश की थी। इसके ठीक उलट जीएसटी की शुरूआत के समय इसकी प्रभावी दर 14.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। बाद में सितंबर 2019 में इसे घटाकर 11.6 प्रतिशत कर दिया गया और मार्च, 20238 में यह 12.2 प्रतिशत हो गया। राजस्व के संदर्भ में, इसे अर्थव्यवस्था के लिए पिछले साल ही 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत (प्रोत्साहन) के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत की जीएसटी दरें दुनिया में सबसे कम हैं। एक उठता हुआ ज्वार सभी नावों को ऊपर उठा देता है। राजस्व में वृद्धि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम होता है, हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि के ऊपर राजस्व संग्रह में होने वाली वृद्धि (या उछाल) एक कर प्रणाली की प्रणालीगत दक्षता की असली परीक्षा होती है। इस मामले में, जीएसटी की शुरूआत के बाद से पहले पांच वर्षों के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद (मौजूदा कीमतों पर) के मुकाबले शुद्ध राजस्व उछाल 1.02 था, जबकि जीएसटी के बाद के सात वर्षों के दौरान यह 1.28 था। यह जीएसटी द्वारा संभव बनाई गई संग्रह संबंधी क्षमता का एक प्रमाण है। निस्संदेह, मासिक आधार पर जारी किए गए राजस्व के आंकड़ों में आमतौर पर सकल संग्रह के आंकड़े शामिल होते हैं। शुद्ध आंकड़े केवल फरवरी, 2024 से प्रकाशित किए गए हैं। हालांकि, जीएसटी की शुरूआत के बाद से प्रत्येक वर्ष की वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और सार्वजनिक रूप से रखी गई है। इन रिपोर्टों में निर्यात के कारण किए जाने वाले जीएसटी रिफंड से संबंधित महीने-वार विवरण शामिल हैं। इसलिए रिफंड संबंधी आंकड़ों की सार्वजनिक दृश्यता, थोड़े अंतराल पर ही सही, बनी हुई है। हम, बिना किसी आधार के, इस दावे की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि जीएसटी परिषद में केन्द्र का ह्रप्रभुत्वह्व है1 जीएसटी की शुरूआत के साथ, केन्द्र और राज्यों ने नए कर के प्रशासन से संबंधित मामलों में, खासतौर पर नीति निर्माण, दरों के निर्धारण, कानूनों/नियमों का मसौदा तैयार करने, अनुपालनों के समन्वय आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी संप्रभुता को एकाकार किया। कभी-कभी इसे राज्यों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में उद्धृत किया जाता है। हालांकि, यह केन्द्र सरकार के लिए भी समान रूप से एक प्रतिबंध है। जीएसटी परिषद ने अपनी समितियों के समर्थन से कई जटिल मुद्दों पर विचार किया है और वह कई ऐसी सिफारिशें लेकर आगे आई है, जिससे कानून के प्रशासन में एकरूपता और दरों की संरचना में स्थिरता आई है। यह सहकारी संघवाद की भावना का एक प्रमाण है। जीएसटी परिषद के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। इसके अलावा, अनुपालनों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी त्रुटियों को दूर करने या छूट को तर्कसंगत बनाने के परिषद के सभी निर्णयों से केन्द्र और राज्यों को समान रूप से लाभ पहुंचा है। उपरोक्त चर्चा से, तीन बिंदु उभर कर सामने आते हैं- सबसे पहले जीएसटी की संग्रह संबंधी क्षमताएं स्पष्ट, सुसंगत एवं प्रारंभिक हैं और मुख्य रूप से अंतर्जात कारकों के कारण हैं। यही बात रिफंड के शुद्ध राजस्व संग्रह को देखने के समय भी लागू होती है। तीसरा, जीएसटी ने अपेक्षाकृत कम कर दरों और बाहरी झटकों के बावजूद राजस्व में लगातार वृद्धि की है। जैसे-जैसे जीएसटी अपने प्रगति के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए दर संरचना का सरलीकरण, जीएसटी के दायरे से बाहर रह गई वस्तुओं को शामिल करना और साथ ही एक कुशल अपीलीय तंत्र जैसे प्रशासनिक मुद्दे। हालांकि अब जबकि जीएसटी के सात वर्ष पूरे हो गए हैं, उत्सव मनाने के लिए काफी कुछ है।

लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

'इसलिए' जरूरी है बफर स्टॉक

गेहूं और चने की खुले बाजार में बिक्री से अनाज और दालों की बढ़ती महंगाई को रोकने में मदद मिली है। बढ़ते जलवायु-संचालित आपूर्ति झटकों और मूल्य अस्थिरता के बीच बफर स्टॉक को अन्य प्रमुख खाद्य पदार्थों तक बढ़ाना समझदारी है। मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए बफर स्टॉक को चावल, गेहूं और चुनिंदा दालों के अलावा तिलहन, सब्जियों और यहां तक कि दूध पाउडर को भी शामिल किया जाए। भविष्य में बाजार स्थिरीकरण के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बनाने के लिए अधिशेष वर्षों के दौरान खरीद बढ़ाने की वकालत की जाती है। बफर स्टॉकिंग जलवायु परिवर्तन से प्रेरित कृषि अनिश्चितताओं से प्रभावित मूल्य अस्थिरता को कम कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को लाभ होगा। दरअसल बफर स्टॉक आवश्यक वस्तुओं के भंडार हैं जो आपूर्ति और मांग में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए बनाए रखे जाते हैं। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान शुरू बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाए गए चावल और गेहूं के बफर स्टॉक प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इन प्रमुख वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता का समर्थन होता है। बफर स्टॉकिंग खाद्य पदार्थों की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने का एक साधन हो सकता है, मुद्रा बाजार के मुकाबले आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के समान। जलवायु-संचालित मूल्य अस्थिरता में वृद्धि-जो अंततः न तो उपभोक्ताओं और न ही उत्पादकों की मदद करती है-केवल खाद्य बफर नीति के मामले को मजबूत करती है। आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों को स्थिर करने के लिए कमी की अवधि के दौरान बफर स्टॉक जारी किया जाता है, जिससे उपलब्धता सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए 2019 में प्याज की कीमत में उछाल के दौरान भारत सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने, कीमतों को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बफर स्टॉक जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्याज सस्ता बना रहे। बफर स्टॉक बनाए रखने से सरकार आपूर्ति की कमी के दौरान कीमतों में भारी वृद्धि को रोक सकती है, जिससे बाजार की मांग संतुलित रहती है । उदाहरण के लिए 2020 में सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक से दालें जारी कीं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उत्पादन में कमी के बावजूद दालें उपलब्ध और सस्ती बनी रहें। बफर स्टॉक बाजार में आपूर्ति और मांग की गतिशीलता को विनियमित करके अत्यधिक मूल्य में उतार-चढ़ाव को सुचारु बनाने में मदद करते हैं। बफर स्टॉक कमी के दौरान बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर मुद्रास्फीति को कम करते हैं, जिससे कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए 2021 में गेहूं और चावल के स्टॉक को जारी करने से भारत में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि मुख्य अनाज उपभोक्ताओं के लिए किफायती रहे। बफर स्टॉक स्थिर बाजार सुनिश्चित करके, अधिक आपूर्ति के कारण कीमतों में गिरावट को रोककर और मूल्य स्थिरता प्रदान करके किसानों की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए: सरकार ने अतिरिक्त दूध खरीदा और किसानों के लिए दूध की कीमतों को स्थिर करने के लिए इसे स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) में बदल दिया, जिससे अधिक आपूर्ति के कारण वित्तीय नुकसान को रोका जा सके। बफर स्टॉक आवश्यक खाद्य पदार्थों तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करते हैं , जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए महामारी के दौरान , गरीबों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने, भूख को रोकने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया था। बफर स्टॉक कीमतों को स्थिर करके और बाजार संतुलन बनाए रखकर आर्थिक झटकों को रोकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता में योगदान मिलता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 2018 के सूखे के दौरान बफर स्टॉक जारी करने से कीमतों को स्थिर करने और आर्थिक स्थिरता का समर्थन करने में मदद मिली, जिससे क्षेत्र में आर्थिक संकट को रोका जा सका। बफर स्टॉक जलवायु-प्रेरित आपूर्ति झटकों के कारण खाद्य उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करते हैं, जिससे जलवायु लचीलापन बढ़ता है। अधिशेष वर्षों के दौरान अतिरिक्त उपज की खरीद करके बफर स्टॉक किसानों को एक स्थिर बाजार और उचित मूल्य प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण आर्थिक स्थिरता में योगदान मिलता है। बफर स्टॉक कल्याणकारी योजनाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करते हैं, जो कमजोर आबादी का समर्थन करके और सामाजिक स्थिरता बनाए रखकर आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) ने कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को भोजन वितरित करने के लिए बफर स्टॉक पर भरोसा किया , जिससे भूख और अभाव को रोककर आर्थिक और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित हुई। चूंकि भारत जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए सरकार द्वारा नियंत्रित बफर स्टॉक कीमतों को स्थिर करने और आर्थिक स्थिरता का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर मुद्रास्फीति को कम करके और कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करके, ये बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन बढ़ाएंगे।

Social Media Corner

सच के हक में...

श्रीमती कमला पुजारी जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने कृषि में उल्लेखनीय योगदान दिया, विशेष रूप से जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और स्वदेशी बीजों की रक्षा करने में। स्थिरता को समृद्ध करने और जैव विविधता की रक्षा करने में उनके काम को वर्षों तक याद किया जाएगा। वह आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने में भी एक प्रकाशस्तंभ थीं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। शांति।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

शुक्रवार को लाठी चली थी, शनिवार को गोले बरसाए गए। हजारों की संख्या में जब पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे, तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने अपनी पीठ बचाने के लिए पुलिस को आगे कर दिया। अभी कल सहायक पुलिसकर्मियों की पीठ पर कोड़े बरसाने के बाद भी हेमंत की हिम्मत कम नहीं हुई और आज पारा शिक्षाओं के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में झारखंड के लोगों को सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए हाथ फैलाकर भीख मांगना पड़ रहा है, और इसके बाद भी क्रूर, अहंकारी, अत्याचारी शासक की हिम्मत तो देखिए, निहत्थे असहाय झारखंडवासियों पर किस तरह से लाठी और गोले दागे जा रहे हैं।

(पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक ज्ञान का वाहक है चातुर्मास

वैदिक काल में चातुर्मास नामक यज्ञ होते थे। चातुर्मास को पर्व, अंग या संधि भी कहा जाता है। चातुर्मास प्रति चौथे मास के अंत में किया जाता है। अतः इन्हें चातुर्मास्य संज्ञा मिली है। संस्कृत भाषा का चातुर्मास्य शब्द ही चातुर्मास और आम बोलचाल में चौमासा हो गया है। आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार चातुर्मास तीन हैं- वैश्वदेव, वरुणप्रघास और साकमेध। कुछ लेखकों ने शुनासीरीय नाम वाला एक चौथा चातुर्मास भी सम्मिलित किया है। वैश्वदेव फाल्गुन या चैत्र की पूर्णिमा पर, वरुणप्रघास आषाढ की पूर्णिमा तथा साकमेध कार्तिक की पूर्णिमा को किये जाते हैं। इनमें तीन ऋतुओं- वसंत, वर्षा एवं हेमंत के आगमन का निर्देश मिलता है। वास्तव में चातुर्मास ऋतु संबंधी यज्ञ है। शुनासीरीय चातुर्मास के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। अब प्रायः वर्षा काल का सूचक वरुणप्रघास चातुर्मास ही रह गया है, जिसके आयोजन साधु-महात्माओं द्वारा कहीं-कहीं होते हैं। वरुणप्रघास शब्द पुल्लिंग है और सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्युत्पत्ति दी है- यव (जौ) अन्न वरुण के लिए है और ये इस कृत्य में खाये जाते हैं। अतः इसका नाम वरुणप्रघास है। यह कृत्य वर्षा ऋतु में आषाढ़ या श्रावण की पूर्णिमा को किया जाता है। वरुणप्रघास का तात्पर्य वर्षा के चार महीनों में वरुण देवता को यज्ञ में हव्य अर्पित करने से है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी या द्वादशी या पूर्णिमा को या उस दिन, जिस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रविष्ट होता है, चातुर्मास व्रत का आरंभ होता है। गरुड़ पुराण ने एकादशी एवं आषाढी पौर्णमासी को चातुर्मास व्रत कहा है। यह चाहे जब शुरू हो, कार्तिक शुक्ल में द्वादशी को समाप्त हो जाता है। चातुर्मास में धार्मिक कृत्यों का संपादन होता था। यायावर संतों की धर्म यात्राएं थम जाती थीं। राजाओं के सैन्य अभियान रुक जाते थे। यह चातुर्मास काल की महत्ता ही है कि पुरातन काल से चले आ रहे महत्वपूर्ण चार पर्वों में होली को छोड़कर तीन पर्व- रक्षा बंधन, विजयादशमी और दीपावली चातुर्मास की अवधि में ही मनाये जाते हैं। चातुर्मास आध्यात्मिक, दार्शनिक और सामाजिक उत्सव थे। स्मृतियों और धर्मशास्त्र के ग्रंथों से साफ है कि सहस्राब्दियों तक इनकी परंपरा अनवरत चलती रही। कालांतर में चातुर्मास के कृत्यों में परिवर्तन होते गये। पौराणिक काल के चातुर्मास वैदिक काल के चातुर्मास से भिन्न हैं। बारहवीं शती में इस्लामी आक्रांताओं के बाद ये समाप्त से हो गये और इनके स्थान पर अन्य धार्मिक कृत्य किये जाने लगे, जिन पर चातुर्मास की छाया देखी जा सकती है। आज चातुर्मास उपेक्षित सा है। इसके बारे में घोर अज्ञान है। यह वेदों से शुरू होता है। इसकी शास्त्रीय परंपरा जो भी रही हो, पर आम जन इसे कर्मकांड से अधिक नहीं मानता। इसकी शाखाएं खुद तना बन गयी हैं। हर शाखा ने वृक्ष का रूप ले लिया और मूल मरता चला गया। पर चातुर्मास सार्वभौम तथा सार्वकालिक है। इसी से यह चला आ रहा है। साधु-संत चातुर्मास में वेदांत के अमृत तत्व को लोगों में बांट देते हैं। चातुर्मास एक परंपरा है। वह धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान का वाहक है। उसका इतिहास किसी से मत पूछिए। यह उसी प्रकार सनातन है जैसे सनातन धर्म है। चातुर्मास के उपकरण वे हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। वे आस्थावान बनने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य होने का मर्म बताते हैं। आनंद की परिभाषा समझाते हैं। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए और गंभीर पापों के फल से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ किये जाते थे। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि अश्वमेध यज्ञ करने से राजा पापमुक्त होते थे। पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन है- पाप की स्वीकारोक्ति, यानी किये गये पापों का व्यक्ति के मुख से उच्चारण। यह स्वीकारोक्ति वरुणप्रघास चातुर्मास से व्यक्त होती है, जिसमें यजमान को अपने द्वारा किये गये दुराचरणों को सबके सामने बोलना पड़ता था।

नीति आयोग का महत्व

केंद्र और राज्य सरकारों को समावेशी विकास के लिए रणनीतिक तथा तकनीकी सलाह मुहैया कर नीति आयोग ने एक प्रमुख संस्था के रूप में अपने को स्थापित किया है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर जब इसका गठन हुआ था, तब यह स्वाभाविक प्रश्न सामने था कि क्या यह अपनी उपयोगिता सिद्ध कर पायेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 केंद्रीय मंत्रियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में संस्था में शामिल किया है। अर्थशास्त्री सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष बने रहेंगे। पुनर्गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नयी सरकार में मंत्रियों का फेर-बदल हुआ है। वैज्ञानिक वीके सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद, शिशु रोग विशेषज्ञ वीके पॉल और अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी संस्था के पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्ण सदस्यों और आमंत्रित सदस्यों के शीर्षस्थ पैनल के अलावा कई विशेषज्ञ, शोधार्थी और विद्वान विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन करते रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, विभिन्न संस्थानों के विद्वान, उद्योगपतियों आदि की शिरकत अलग-अलग बैठकों में समय-समय पर होती रहती है। योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग की कार्यशैली अधिक लचीली और समावेशी है। आयोग सरकारों को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, पर्यावरण आदि विभिन्न विषयों पर नीतियां बनाने में सलाह मुहैया कराता है। इसके प्रमुख कार्यों में सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन भी है। विकास से संबंधित विषयों पर शोध एवं विश्लेषण के कार्य के साथ-साथ सरकारों को आयोग उनकी क्षमता बढ़ाने में योगदान देता है। हालांकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और कई मंत्री आमंत्रित सदस्य हैं, पर इसकी कार्यशैली स्वायत्त है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

The sad tale of an IAS probationer

PUJA Khedkar got an all-India rank of 821 in the UPSC examination of 2022, yet she was selected for the IAS, the premier civil service in the country. No wonder the standards have fallen. Should there not be a cut-off point below which entry to the IAS, at least, not be allowed?Khedkar belongs to the Vanjari community, which predominates in Bheed district of Marathwada and is prominent in the adjoining Ahmednagar district of western Maharashtra. The community is essentially pastoral and is classified as OBC (Other Backward Classes). Gopinath Munde, former Deputy Chief Minister of Maharashtra, hailed from this community.

There is another community with a deceptively similar name, Banjara, located prominently in Kinwat taluka of Nanded district in Marathwada and in the adjoining taluka in Yavatmal district of Vidarbha. The Banjaras were nomads till very recently. Hence, they have been classified as tribals and are entitled to reservation under the Scheduled Tribes category, which is allotted 7.5 per cent of the government jobs as against the 15 per cent quota enjoyed by Scheduled Castes.

The OBCs were included in the reservation pool after the Mandal Commission report, which was accepted during the Prime Ministership of VP Singh. The OBCs, being numerically larger, have been allotted 27 per cent of the vacancies in government jobs.The criterion of the 'creamy layer' was conceptualised to keep out those in the reserved categories who had gained from reservation. They had sent their children to the best schools and would have established a class within the category. Unless a concept like the 'creamy layer' was introduced in order to enable other neglected members of the category to compete and share the spoils, only the creamy layer would benefit.Presently, those whose parents earned less than Rs 8 lakh per year were excluded from the 'creamy layer'. Khedkar's father was an officer in the Pollution Control Board. Over the years, he seemed to have earned some Rs 40 crore and acquired assets like land and automobiles which he was forced to declare to the Election Commission because of his entering the electoral arena during the 2019 Assembly elections in Maharashtra. Yet, his daughter claimed to be a non-creamy layer candidate when appearing for the civil services examinations.She also claimed to be visually impaired. There is a provision of 2 per cent reservation for the physically impaired, a category in which the visually challenged also fall. This claim had to be ratified by a board of doctors of AIIMS, New Delhi. Though she was given dates for the test more than once, she failed to appear before the board.

I don't know if she tried to pass off as a tribal candidate instead of an OBC by confusing Vanjari with Banjara. The inquiry that has been ordered will pinpoint her falsehoods, if any. And if there are attempts to obfuscate, she should be peremptorily discharged. In fact, she would need to be prosecuted for cheating if any of her claims is proved false.The entitlements claimed by the probationer are simply outrageous. I have come across many entrants to the IAS and the IPS in recent decades who have joined the services with the express purpose of enriching themselves through irregular and illegal means. But I have not heard of a probationer flaunting a BMW or an Audi, as Khedkar is reported to have done, and deigning to use a red beacon on that car to assert her importance.These are traits that should have been noticed even earlier at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in Mussoorie. How did these traits escape the notice of the academy's staff and its director? It is incumbent on the director to advise the government to get rid of such misfits at the training stage itself. It needed the probationer to usurp the anteroom of a serving state service officer during his absence to show her true colours. At least now, the government should act swiftly to get rid of a probationer who is not in the service to serve the people but to be waited on. The academy has recalled her. That indicates appropriate action has been decided.The All-India Service Rules provide the authorities with enough scope to rid the administration of such misfits. I fail to understand why the government is so tolerant. The IAS and IPS officers will perforce interact with the local populace throughout their careers.

Strict enforcement of traffic rules can build respect for the law

Better adherence to traffic rules reduces accidents, lowering healthcare costs and economic losses.

AMERICAN author Robert Fulghum reminds us: "Every time you break a traffic law, you say something about yourself. It says that the rules are for other people." The Mumbai BMW hit-and-run incident — in which the accused is the son of a political leader — and the Pune Porsche case starkly highlight this issue. Punjab recently initiated a project to instal CCTV cameras for monitoring traffic and enforcing road discipline. While compliance may arise out of fear, it is expected to evolve over time into a societal norm embraced by the community.Obeying and enforcing traffic rules go beyond ensuring better traffic flow and reducing the number of accidents. Adhering to traffic rules cultivates responsibility and discipline, encouraging mindfulness of one's actions. This discipline extends beyond driving, fostering a more ethical society. According to the World Health Organisation (WHO), enforcing traffic rules enhances road behaviour, promoting respect and self-discipline.Consistently enforcing traffic rules establishes them as social norms, encouraging a culture of law-abiding behaviour and reducing lawlessness. Effective enforcement, as highlighted by the European Commission report on 'Traffic Law Enforcement across the EU', forms a social environment in which following the rules is the standard. Obeying traffic rules promotes cooperation among road users, enhancing community and collective responsibility. This cooperation, as backed by the Journal of Safety Research, leads to higher levels of civic engagement and a more cohesive society.Adherence to traffic rules promotes a society of good Samaritans. This principle encourages individuals to help others in distress, nurturing empathy and responsibility towards safety and reflecting a broader societal value system of compassion and cooperation. A 2017 study by the American Psychological Association on pro-social behaviour found that people who consistently followed traffic rules were more likely to volunteer in their communities and help others.

This behaviour is directly correlated with overcoming the bystander effect in crime situations. Cultivating a habit of intervening, such as stopping to assist in case of an accident, encourages individuals to take proactive steps in helping or reporting the crimes they witness. This proactive mindset reduces ambiguity and hesitation, aligning with the psychological principle of helpfulness.

A fair and consistent enforcement of traffic rules promotes justice and equality, ensuring that all individuals are held to the same standards. Research by the Institute for Transportation and Development Policy suggests that equitable traffic enforcement builds public trust and ensures equal protection under the law. Enforcing traffic rules educates both the young and the old about the importance of regulations in maintaining safety and order. A report by the US National Highway Traffic Safety Administration underscores the role of traffic

education in schools to instil respect for rules from an early age.Data supports the notion that traffic rule enforcement is both effective and broadly accepted. According to the WHO, countries with stringent traffic law enforcement experience lower rates of road accidents and fatalities. Additionally, a report by the European Commission found that effective enforcement of traffic laws leads to better overall compliance with social norms and a more disciplined populace.Consistent enforcement of traffic rules leads to smoother traffic flow, reducing stress and anxiety while driving. According to research by the American Psychological Association, predictable and orderly traffic conditions positively impact one's mental wellbeing.Better adherence to traffic rules reduces accidents, lowering healthcare costs and economic losses. A study by the International Road Assessment Programme found that improved road safety through better enforcement could save billions of dollars globally. Obeying traffic rules, like speed limits, enhances fuel efficiency and reduces emissions, promoting environmental sustainability. The Environmental Protection Agency states that regulated traffic flow significantly cuts vehicle emissions, aiding in combating air pollution and climate change.

Following and implementing traffic rules is perhaps the easiest and most effective way to instil discipline in a large number of people. Traffic rules are universally recognised and accepted because their benefits are immediate and visible: safer roads, fewer accidents and a more efficient traffic flow. Unlike other forms of regulations, traffic laws do not typically face significant opposition because they are clearly linked to public safety and welfare.

Everyone understands the importance of traffic safety, and the consequences of non-compliance are often immediate and severe. This universal understanding makes it easier to enforce these rules without encountering the resistance that other types of regulations might face.

Moreover, the enforcement of traffic rules does not just lead to safer roads. It also creates a culture of discipline and respect for laws. This indirect benefit is significant. As individuals comply with traffic laws, they internalise the importance of following regulations in general. This extends beyond one's driving behaviour to other aspects of life, leading to a more law-abiding and cooperative society.

Traffic rules also present a unique opportunity to enforce discipline on a massive scale. Unlike many other laws that target specific groups, traffic regulations apply to everyone, regardless of one's age, gender or socioeconomic status. This universality ensures that the principles of discipline and cooperation are instilled in all segments of society. Furthermore, the visibility of traffic law enforcement, such as through police presence and CCTV cameras, reinforces the notion that laws are meant to be followed, thus promoting a culture of complianc.Enforcing traffic rules is a universally accepted and effective means of promoting discipline, respect for laws and social cooperation. It stands out as an approach that encounters minimal resistance while delivering significant benefits, not only in terms of road safety but also in developing a

Karnataka quota Bill

Congress govt makes welcome retreat

SCATHING criticism from business and industry leaders has forced the Karnataka Government to put the contentious reservation Bill for Kannadigas in private firms on hold. The Karnataka State Employment of Local Candidates in the Industries, Factories and Other Establishments Bill, 2024, was cleared by the state cabinet on Monday; however, the ensuing uproar made CM Siddaramaiah claim that the final decision would be taken after comprehensive discussions. As per the Bill, 'any industry, factory or other establishments shall appoint 50 per cent of local candidates in management categories and 70 per cent in non-management categories'. The CM had even tweeted about 100 per cent reservation for Kannadigas in C and D grade posts in private institutions of the state, but he was quick to delete the post.It's baffling that Karnataka, India's tech hub and one of the best-performing states in terms of ease of doing business, has come up with this regressive Bill. NASSCOM (National Association of Software and Service

Companies) has cautioned the Congress government that the 'restrictions could force companies to relocate as local skilled talent becomes scarce'. The southern state has failed to learn a lesson from the Haryana fiasco. The Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020, which mandated 75 per cent reservation in private sector jobs for residents of the state, was struck down by the Punjab and Haryana High Court in November 2023. Andhra Pradesh and Jharkhand have also got their fingers burnt with similar legislation.

The 'vocal for local' slogan might have gained currency in recent years, but any compromise on merit, talent and skills for the sake of political gains is enough to put off investors. The TDP government in Andhra, looking to cash in on neighbouring Karnataka's potential own goal, has invited NASSCOM to expand or relocate its businesses to Vizag. Amid the fierce competition between states over investments, Karnataka would be well advised to give the Bill a quiet burial.

Onus on Punjab to reform land leasing ecosystem

An overwhelming number of informal tenants depend upon commission agents, landowners and money-lenders for undertaking farm operations.

THE agricultural land lease market in Punjab has witnessed phenomenal growth and expansion. It covers all agro-climatic zones, districts, principal crops and classes of landholders. It has been the outcome of cumulative pressure and interaction among endogenous and exogenous forces, such as high-end mechanisation, commercialisation, technological advancements, assured public procurement, support prices, extensive market network and overall modernisation of the state agricultural system. The land tenurial system in the state changed drastically with the advancement of agriculture as compared to the official programme of land reforms, which basically remained confined to ownership ceiling, abolition of intermediaries, grant of occupancy rights to 'tenants at will' and consolidation of fragmented holdings. The land reforms, as envisaged and implemented in the initial decades of agrarian reforms, gradually became redundant, and land relations adjusted to the market-driven system of production.

The private-cum-individualised ownership of cultivable land got a firm rooting in the state. Farm households, as private producers, took production decisions anchored in the market principle of profit maximisation. This required scaling up the size of the holding, and hence, land leasing emerged as the only viable and handy option. The centuries-old practice of share cropping or in-kind tenancy vanished from the agrarian scene of the state. The institution of land tenancy off-loaded its feudalistic/semi-feudalistic/social embeddedness. The traditional practice of lease-in by marginal farmers/resource-poor peasants/pure tenants from big landlords for the purpose of survival or subsistence ended in due course.A new form of commercial/capitalistic/reverse tenancy has gained ground. It is a market-driven venture spearheaded by enterprising farmers who 'lease in' land from other classes of landholders. These are essentially middle-sized farmers with a comprehensive set of farming, organisational, managerial and supervisory skills and deep connections in the input, credit and labour markets.

The supply of land for the purpose of leasing out is on the rise due to a number of factors — discontinuation of 'self-cultivation' by a good number of farm households, settling of families in the urban vicinity, emigration to other countries, less availability of able-bodied persons for handling agricultural operations, adoption of non-farming occupations, joining the services sector, etc.Land leasing involves getting access to land through a lease contract which bestows economic ownership, not proprietary ownership, on the lessee on the basis of mutually agreed terms and conditions. This results in the transfer and use of physical assets for an economic consideration. Thus, a lease is a transfer of an asset for a limited time in return for a periodic payment called rent. In the economic context, the terms rent and lease imply the same thing but for a difference in the duration — the former is for a shorter duration and the latter for a longer one. Lease agreements, if written and duly registered, are regulated by the lease contract, which spells out the obligations and rights of the parties concerned, and hence are enforceable.

In 2015, the NITI Aayog constituted an expert committee on land leasing under the chairmanship of T Haque. Subsequently, the committee submitted the draft of the Model Agricultural Land Leasing Act, 2016. The Act argued for the legalisation of land leasing to ensure security of land ownership rights for landowners and security of tenure for tenants, and

laws in Punjab, the state Department of Revenue, Rehabilitation and Disaster Management constituted the five-member Revenue Commission under the chairmanship of Justice SS Saron, a retired judge of the Punjab and Haryana High Court, in February 2018. The commission drafted the Punjab Land Leasing and Tenancy Bill, 2019, for determining the owners/lessors and lessees' rights and obligations towards each other in a fair and justifiable manner, and without impacting the proprietary and ownership rights of the owners of the land while giving their lands on lease.In July 2019, the state cabinet decided to refer the Bill to a cabinet sub-committee headed by the Finance Minister and having the social security and revenue ministers as members. The commission answered in detail the questions raised by the sub-committee and concluded that "in the circumstances, it would be in the fairness of all and a feather in the cap of Punjab to be a pioneer in the field of enactment of a land leasing and tenancy legislation; besides, this would entail financial incentives to the state". The commission observed that the restrictions on lease holdings resulted in concealed tenancy, and informal tenants were more insecure.

The tenancy market in the state has been operating on an annual basis in the rental mode with oral contracts and cash deals, which obstruct capital formation in the farm sector. The informal tenant has no long-term interest and incentive to make any durable investment in rented land. And it is not possible to raise formal credit, get compensation for crop damage, receive official payment for selling the produce, avail government schemes and subsidies, and undertake risky ventures for producing high-value crops beyond the ambit of the MSP regime. An overwhelming number of informal tenants depend upon commission agents/money-lenders and landowners for undertaking agricultural operations. The situation demands the creation of an enabling framework to promote 'professional tenancy' through long-term written and registered leasing contracts, based on proper incentivisation, hassle-free functioning with a stipulated entry and exit framework. This has been the rationale and vision articulated by the Revenue Commission in its final draft Punjab Land Leasing and Tenancy (Safeguarding Rights and Enforcing Liabilities of Lessor and Lessee) Bill, 2021; this needs to be further taken up to formalise the long-term land lease market for the next-level transformation of the agriculture sector in the state.

A massive tech outage is causing worldwide disruptions. Here's what we know

The company says the problem occurred when it deployed a faulty update to computers running Microsoft Windows, noting that the issue behind the outage was not a security incident or cyberattack.

New Delhi Much of the world faced online disarray Friday as a widespread technology outage affected companies and services across industries — grounding flights, knocking banks and hospital systems offline and media outlets off air.At the heart of the massive disruption is CrowdStrike, a cybersecurity firm that provides software to scores of companies worldwide. The company says the problem occurred when it deployed a faulty update to computers running Microsoft Windows, noting that the issue behind the outage was not a security incident or cyberattack.CrowdStrike has said a fix is on the way. Still, chaos deepened hours after the problem was first detected.

Here's what you need to know.

How did Friday's 'blue screen' outage emerge?Friday's disruptions began when a faulty update was pushed out from CrowdStrike for one of its tools, "Falcon." In a statement about the ongoing situation, the company said the defect was found "in a single content update for Windows hosts" — noting that Mac and Linux systems were not impacted.But, because scores of companies rely on CrowdStrike for their security needs with Windows as their operating system, the consequences of this kind of technical problem have been far-reaching. As a result, affected computer after computer showed the "blue screen of death" error message.

Long lines formed at airports in the U.S., Europe and Asia as airlines lost access to check-in and booking services during

peak summer travel — disrupting thousands of flights. Banks in South Africa and New Zealand reported outages impacting payments. Some news stations, particularly in Australia, were unable to broadcast for hours. And hospitals had problems with their appointment systems, leading to delays and sometimes cancelations for critical care, while officials in some U.S. states warned of 911 problems in their areas.

Elsewhere, people experienced more minor inconveniences, including trouble ordering ahead at Starbucks, causing long lines at some of the coffee chain's stores. Some billboards in New York City's famous Times Square also went dark.Experts stress that Friday's disruptions underscore the vulnerability of worldwide dependence on software that comes from only a handful of providers."It is an 'all our eggs are in one basket' situation," Craig Shue, professor and computer science department head at Worcester Polytechnic Institute, said in emailed commentary. "This lets us make sure our 'basket' is high quality: the software provider tries to identify threats and respond to them quickly. But at the same time, if anything goes wrong and the basket fails, we have a lot of broken eggs."

What is CrowdStrike?

CrowdStrike is a U.S. cybersecurity company that provides software to companies around the world and across industries. It bills itself as being the globe's most advanced cloud-based security technology provider.

India's Forex Reserves Hit Record USD 666.85 Billion, Driven By Surging Gold And Foreign Currency Assets

New Delhi. India's foreign exchange reserves have surged to a record high, reaching a new peak of USD 666.85 billion, according to data from the Reserve Bank of India (RBI). The data highlights an increase of USD 9.69 billion in just one week, as of 12 July, surpassing the previous high of USD 657.2 billion. The reserves have been rising intermittently for some time now.

The RBI data reveals that India's foreign currency assets (FCA), the largest component of forex reserves, rose by USD 8.3 billion to USD 585.47 billion. Additionally, gold reserves increased by USD 1.2 billion, reaching USD 58.66 billion.PauseAccording to a recent RBI report, India's foreign exchange reserves are now sufficient to cover over 11 months of projected imports. In the calendar year 2023, the RBI added approximately USD 58 billion to its foreign exchange reserves. In contrast, in 2022, India's forex reserves declined by a cumulative USD 71 billion.Forex reserves, or foreign exchange reserves (FX reserves), are assets held by a nation's central bank or monetary authority, typically in reserve currencies such as the US Dollar, and to a lesser extent, the Euro, Japanese Yen, and Pound Sterling.

The country's foreign exchange reserves last reached an all-time high in October 2021. Much of the subsequent decline can be attributed to the increased cost of imported goods in 2022. Additionally, the relative fall in forex reserves has been linked to the RBI's market interventions to manage the uneven depreciation of the rupee against a surging US dollar.The RBI frequently intervenes in the market through liquidity management, including the sale of dollars, to prevent steep depreciation of the rupee. The RBI closely monitors the foreign exchange markets and intervenes only to maintain orderly market conditions by containing excessive volatility in the exchange rate, without reference to any pre-determined target level or band.

Wipro profit up 5%; to hire 12K freshers in 2025

BENGALURU: Wipro beat Street estimates and posted a 4.6% rise in its consolidated net profit for the June quarter at Rs 3,003 crore as against Rs 2,870 crore in the year-ago period.However, it missed revenue expectations and its consolidated revenue fell 3.7% to Rs 21,964 crore as against Rs 22,831 crore in the same quarter last year due to softness in certain geographies. Srini Pallia, CEO and MD, said in the first quarter, the company didn't see a major shift in demand environment. "Clients remained cautious and discretionary spending continued to be muted," he said.Large deal bookings in the first quarter stood at $1.2 billion and IT services operating margin was at 16.5%, a rise of 0.4% YoY. Wipro has guided sequential revenue growth in the range of (-)1% to + 1% in constant currency terms. The company had kept the revenue guidance to (-) 1.5% to + 0.5% for Q1FY25.When asked whether Wipro is planning for any acquisition in FY25, the CEO said, "M&A (mergers and acquisitions) is something that we will constantly look out and we will do the right M&A at the right time. That's part of the strategy and we have a

solid M&A team and as an organisation we have been acquisitive and we will continue to do that."Pallia said in Q1 the company maintained positive momentum in its Capco business, achieving a sequential growth of 3.4%. The company acquired Capco, a global management and tech consultancy to the banking and financial services industry, for $ 1.45 billion in 2021.After a break of a year the company has started on boarding freshers from the campus. The company's Chief Human Resources Officer Saurabh Govil said the firm has onboarded about 3,000 freshers in the first quarter and will add 10,000 to 12,000 in the current fiscal.

Friday crash wipes out Rs 8L crore from domestic equity market

NEW DELHI. Snapping a four-day winning rally, India's equity market benchmarks – BSE Sensex and NSE Nifty50– took a beating on Friday due to the global sell-off, triggered by operating system issues that caused devices to crash worldwide. Premium valuation concerns and investors deciding to book profit ahead of the union budget due on Tuesday next week also dampened sentiments.

At close, the Sensex was down 0.91% at 80,604 and the Nifty was down 1.09% at 24,530. The selling was so widespread that only 858 shares registered on the BSE gained while 3,071 shares declined and 81 were unchanged. The broader markets logged a decline for the second straight day as midcap and smallcap indices fell 2.3 and 2.2%, respectively.In total, investors lost almost Rs 8 lakh on Friday as the market capitalization of BSE-listed firms fell to Rs 446.38 lakh crore on Friday against Rs 454.32 lakh crore in Thursday's session."The global IT outrage has led to disruptions in various Indian industries. The overvalued market is also experiencing profit booking ahead of the budget next week. The recent performance has been bullish in anticipation of pro-industry and populist measures," said Vinod Nair, Head of Research, Geojit Financial Services.Ajit Mishra – SVP, of Research, Religare Broking said that this decline signals caution ahead of the Union Budget, as participants chose to book profits.

HCLTech links employee leaves to office attendance under new policy: Report

NEW DELHI.T HCLTech is set to implement a new policy that ties employee leaves to their office attendance, reported moneycontrol.com quoting sources.The policy aims to enforce a three-day work-from-office rule as companies push to bring employees back to the workplace after the pandemic.

Under the new policy, HCLTech employees must work from the office at least three days a week and at least 12 days a month.If employees fail to meet this requirement, their leaves will be deducted for each day they are absent. This policy follows the company's shift to a hybrid work model five months ago, which required employees to return to the office three days a week.

An anonymous employee quoted in the moneycontrol.com report mentioned that the HR department has begun communicating this update via emails, and the policy is already in effect.

"Once our leaves are over, this could lead to loss of pay," the employee added.

As of now, HCLTech employees with less than three years of tenure are eligible for 18 annual leaves and one personal leave. Employees with more than three years' tenure receive around 20 annual leaves and two personal leaves.

"Our hybrid work policy provides flexibility where people in middle and senior-level management follow any three-days-a-week work-from-office arrangement which supports collaboration. All other employees follow the working arrangements necessary to meet client commitments, planned by their respective managers," an HCLTech spokesperson told the publication.Back to officeInitially, IT services companies embraced a hybrid work model, allowing remote work options.However, as most of the industry's current workforce joined during the Covid pandemic and had never been to their offices, companies now believe that office attendance will help build social capital among new employees and improvecollaboration on projects.Before HCLTech, TCS had already linked its quarterly variable pay component to office attendance.

In April, TCS required a minimum 60% office attendance for employees to be eligible for variable pay, with strict disciplinary actions for consistent violations.TCS's policy resulted in nearly 70% of their employees returning to the office.

Confused With PF Withdrawal EPFO Comes With New Initiative To Help Members

New Delhi. The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has around seven crore active subscribers and it's setting up a 24/7 multilingual contact center for them. This center will be available every day of the year and provide a single point of contact for registering complaints and seeking help with any issues. This initiative aims to make it easier for subscribers to get the support they need, whenever they need it.

This decision follows recent acklash on social media about delays in resolving complaints and an increase in rejected settlement claims, as reported by The Indian ExpressThe EPFO has issued a tender to establish this 24/7 contact center which will be open every day of the year. The aim is to staff it with "quality people and create a robust system that will replace the current grievance registration portal (EPFiGMS) with a more advanced and sophisticated solution." (Also Read: Microsoft Outage: SBI Reports Systems Unaffected And Working) SmoothlyHow This Will Benefit People?EPFO stated that their aim is to handle grievances across multiple channels, such as helpline numbers, landline phones at various offices, walk-ins, grievance registration portals, WhatsApp, social media (including Facebook, Twitter, and Instagram), physical mail, ChatBot, the UMANG app, and emails. By connecting the EPFO's head office with its zonal and regional offices, the system will enable efficient problem-solving. Furthermore, it will proactively address stakeholders' issues and keep them informed in real-time.

Multilingual Support in 23 Languages

The new contact center will support 23 languages, making it accessible to more people. These languages include Hindi, English, Assamese, Maithili, Kashmiri, Bodo, Dogri, Gujarati, Kannada, Konkani, Manipuri, Marathi, Bengali, Malayalam, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Santhali, Tamil, Telugu, and Urdu.EPFO plans to upgrade its Helpline into an Integrated Grievance Management System with new software for registering complaints. This system will include tools to oversee and enhance subscriber satisfaction by resolving grievances quickly. By automating processes in its offices, EPFO aims to speed up service and improve quality, making it easier to handle common requests from start to finish.

The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) which was launched in March 1952 stands as one of the earliest security schemes for workers in Independent India. This crucial initiative came into effect just 830 days after the adoption of the Constitution.

Global IT meltdown: Antivirus update causes massive disruptions

/MUMBAI/BENGALURU . AIRLINES, banks, media outlets, and financial institutions across the world were on Friday thrown into turmoil by one of the biggest IT crashes in recent histoy, caused by an update to an antivirus programme.The mass IT outage came after some widely used Microsoft 365 applications and services shut down for hours as a result of the update. There were unprecedented chaos in major cities, including in India, with flights grounded, communication shut down, and shops closed.Millions encountered the Blue Screen of Death (BSOD) error, causing sudden system shutdowns or restarts. Microsoft, which said it was actively working to fix the outage, attributed the BSOD issue to a recent update by cybersecurity firm CrowdStrike, which admitted that its action affected Windows devices.In India, almost all the airlines and major airports were affected as they struggled to provide online booking, web check-ins, and flight status updates. IndiGo cancelled around 200 flights across the country.SpiceJet, Air India, Akasa, and Vistara also faced disruptions due to a technical error in Microsoft Azure, the cloud computing platform that powers critical systems. Throughout the day, airlines were seen doing manual check-ins and issuing hand-written boarding passes.Operations at key airports such as Delhi, Mumbai, Chennai and Bengaluru were badly hit, leaving thousands of passengers stranded. Aviation minister Ram Mohan Naidu said his ministry and Airports Authority of India (AAI) are actively managing the situation.Banking regulator RBI in a statement said that critical systems of most banks are not in cloud and that only a few banks are using the CrowdStrike tool, which created the chaos. "Our assessment shows that only 10 banks and NBFCs had minor disruptions, which have either been resolved or are being resolved. Overall, the Indian financial sector in the Reserve Bank's domain remains insulated from the global outage," an RBI statement read.Auto major Maruti Suzuki India said it had briefly halted production and dispatch operations due to the outage.Although many IT employees found it difficult to log into Microsoft applications on Friday, no major setbacks were reported for the IT industry except production downtime. "Those who were using Microsoft Azure were not able to log in," an IT employee said.Meanwhile, in a statement around 7 in the evening, CrowdStrike said that the issue has been identified, isolated and a fix has been deployed.What exactly happened and how it created chaosMicrosoft said the issue began at 1900 GMT on Thursday, after a defective update to CrowdStrike Falcon, an IT solution designed to protect Windows systems, ended up crashing the systems instead

Budget 2024: Stock market may face bigger crash than Lok Sabha election result day if...

NEW DELHI. The stock market could face a sharper decline than the post-election reaction if Budget 2024 introduces any unfavorable changes with respect to the capital gains tax for equities, said Chris Wood, global head of equity strategy at Jefferies.

In his weekly note to investors, GREED & Fear, he warned that adjustments to both long-term and short-term capital gains tax in the upcoming budget, set for announcement on July 23, could trigger a more significant correction than the one following the Lok Sabha election outcome on June 4, when the BJP lost its majority but formed a government with coalition partners."The view is that the re-elected government is unlikely to make such a move because of the reduced mandate. Still if that view turns out to be wrong, and the capital gains tax is increased materially, it will likely trigger a bigger correction than what occurred post the election," Wood said.In addition, Wood asserted that despite the rally in equities over the past few years, India is still in the early stages of developing an equity culture.His confidence in the Indian stock market's resilience is driven by the increasing participation of retail investors, which he expects to continue. According to Wood, the domestic stock market remains one of the most promising globally, even after the BJP's loss of majority earlier this year.

Read Full Budget 2024 Coverage

Wood highlighted how the stock market was quick to bounce back after the massive crash on Lok Sabha election result day."The stock market only corrected for one day and has since risen by 13.3% (since June 4). This underscores the power of the retail investor phenomenon, where retail investors bought as professionals sold, and so far, the retail investors have been right," Wood said."The Indian market has fundamentally changed, becoming more domestically driven. In GREED & fear's view, India remains in the early stages of the growth of what could be termed the cult of equity," Wood added.Citing these factors, Wood advised investors against selling in the event of a correction, except for short-term or tactical reasons.

Chris Wood's budget expectations

On the upcoming full budget, Wood said it will be closely watched for any signs of populism to meet the demands of the two

minority parties in the BJP coalition. Wood suggests that the budgetary allocation for such demands will likely be less than feared.Wood recently shared his views on capital gains tax and its potential impact ahead of the Union Budget 2024 in a recent market town hall hosted by CNBC-TV18.He highlighted that any significant increases in capital gains tax could negatively impact the market more than previous events like post-election fluctuations.Wood also pointed out that several markets, including Hong Kong, do not impose capital gains tax, suggesting that having no capital gains tax could be beneficial as it would encourage more investments and market growth.He believes that if capital gains tax is maintained, it should favour long-term investments by having a substantial difference between the tax rates for long-term and short-term holdings.Investors want capital gains tax reliefIt may be noted that experts and industry bodies have long advocated for simplification and uniformity in the capital tax regime to enhance transparency and ease compliance.

One proposal under consideration is to increase the tax-free long-term capital gains (LTCG) ceiling from the current Rs 1 lakh to Rs 2 lakh.According to a note shared by EY, a simplified capital gains tax regime is expected. "An overhaul of the capital gains tax structure, including changes in tax rates and computation methods, is required. Similar to immoveable property, the government should provide a tolerance limit of at least 10% of actual consideration for normative taxation purposes for the transfer of unlisted shares," EY said.

Flight operations 'smooth', backlog being cleared: Centre after IT outage

Sharing an update on airline operations, the Civil Aviation Ministry said all issues related to travel adjustments and refund processes were being taken care of.

New Delhi: The Ministry of Civil Aviation on Saturday said that flight operations were smooth and airline systems were back to normal across all airports a day after a global Microsoft outage led to flight cancellations and chaotic scenes at check-in counters. In a statement, the ministry said all issues related to travel adjustments and refund processes were being taken care of."Since 3 am, airline systems across airports have started working normally. Flight operations are going smoothly now. There is a backlog because of disruptions yesterday, and it is getting cleared gradually. By noon today, we expect all issues to be resolved," the Aviation Ministry said.owever, the IGI Airport in Delhi faced significant disruptions on Saturday morning as the Digi Yatra system, a biometric-based boarding system, remained non-operational. Long queues were observed at the departure terminals as passengers struggled to check in manually. Airport authorities have deployed additional staff to assist travellers and manage the

congestion.

Between 6-7 am today, the system continued to experience glitches while issuing boarding passes. However, the scenario improved later in the day.In contrast to the chaos, most flights managed to stay on schedule, with the waiting period at Terminal 3 departures averaging around 3 to 5 minutes. The situation marked a significant improvement from Friday when the global outge led to widespread delays.The global IT outage had far-reaching effects, disrupting airline operations worldwide. Airports and airlines rely heavily on Windows-based systems for a variety of functions, including check-ins, baggage handling, and security clearances. The outage highlighted the vulnerability of critical infrastructure to software issues.At IGI Airport, the impact was immediate and severe. The disruption of Digi Yatra forced a return to manual processes. This not only slowed down operations but also increased the strain on airport staff and resources.The impact of the outage of Microsoft 365 and Azure services saw hundreds of flights, including those by Indigo, Air India, SpiceJet and Akasa Air, getting delayed and several were cancelled as airline operators switched to manual processes.At the Delhi airport, more than 400 flights faced delays. Several passengers took to social media to post images of handwritten boarding passes.

500 Para Commandos To Hunt Pakistani Terrorists In Jammu After Attacks

New Delhi: In view of the infiltration of highly trained Pakistani terrorists in the Jammu region, the Indian Army is readjusting its deployments in the area as per intelligence inputs and security requirements.

The Indian Army has deployed around 500 Para Special Forces commandos in the area to hunt down the 50-55 terrorists from Pakistan who have entered the region to revive terrorism there, defence sources told news agency ANI.The intelligence agencies have also bolstered their apparatus in the area and are working to take out the terrorist support infrastructure there

including overground workers who support terrorists, they said.The Army has already brought in troops to the area including one brigade strength of around 3,500-4000 personnel to counter Pakistan's proxy aggression here, they said.

The Army brass on the ground has been working towards strategies to search and destroy the terrorists, who are equipped with the latest weaponry and communication equipment, they added.The Army already has an existing counter-terrorist infrastructure in the area with presence of two forces of the Rashtriya Rifles including the Romeo and Delta forces along with other regular infantry divisions in the area, they said.

Government Lists 6 New Bills For Upcoming Parliament Session. Details Here

New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) has arrested Haryana Congress MLA Surender Panwar in an "illegal" mining-linked money-laundering case, official sources said on Saturday. The 55-year-old legislator was taken into custody in the early hours in Gurugram. He will be produced before a special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court in Ambala where the central agency will seek a custodial remand, the sources said.The agency had raided the premises of the MLA in January on the charges of "large-scale illegal mining" in the Yamunanagar area of the state.It had then arrested former Indian National Lok Dal (INLD) legislator from Yamunanagar, Dilbag Singh, and one of his associates,

Kulwinder Singh, in the case.

Assembly elections for Haryana's 90 seats are slated to be held later this year.The money-laundering case stems from several FIRs registered by the Haryana Police for probing alleged illegal mining of boulders, gravel and sand that took place in the past in Yamunanagar and nearby districts in spite of a ban imposed by the National Green Tribunal (NGT).The ED is also probing an alleged fraud in the "e-Ravana" scheme, an online portal that was introduced by the Haryana government in 2020 to simplify collection of royalties and taxes and prevent tax evasion in mining areas.It is estimated, as per the ED, that the alleged illegal mining generated slush funds of about ? 400-500 crore over the last few years.

Pistol That Puja Khedkar's Mother Waved At Farmers In Viral Video Seized

Mumbai/New Delhi: Days after the mother of controversial probationary IAS officer Puja Khedkar was arrested, Pune Police has seized a pistol and three bullets from her house, which she used to allegedly threaten some Maharashtra farmers.Manorama Khedkar was arrested from Maharashtra's Raigad district on Thursday in connection with the viral video in which she is seen brandishing a firearm and threatening some villagers, reportedly over a land dispute.Police have also seized the SUV seen in the viral video which has sparked public outrage.

Ms Khedkar faces multiple charges, including attempt to murder.The footage shows her in a heated exchange with a farmer, demanding to see land documents allegedly in her name. As tensions escalated, she waved the firearm threateningly before quickly concealing it upon noticing a

camera recording the encounter.The video that has put Manorama Khedkar in trouble emerged amid the row surrounding her 34-year-old daughter Puja Khedkar.The 2023-batch trainee IAS officer made headlines a few weeks ago when Pune collector Suhas Diwase wrote to Maharashtra Chief Secretary Sujata Saunik, flagging several demands that she was not entitled to during her probation.This complaint set in motion a chain of events that led to shocking revelations. Questions were raised over how she cleared the tough selection process for UPSC. She was found to have availed of relaxation for physical disability and OBC candidacy, but allegations of her not being eligible for such relaxations surfaced.Her two-year training has now been put on hold, and her selection into the IAS is being probed by a panel formed by the Centre.

Air India relief flight lands in San Francisco with passengers stranded in Russia

New Delhi: Two days after making an emergency landing in Russia, the stranded passengers of Air India's United States-bound flight arrived at San Francisco in another aircraft from Krasnoyarsk International Airport (KJA).The relief flight, which took off from Russian Airport, arrived in San Francisco, with all the stranded passengers, Air India stated in a post on X."We thank the DGCA, Government of India, Embassy of India in Russia, the Russian authorities, the Transportation Security Administration (TSA), U.S. Customs and Border Protection, Krasnoyarsk International Airport, and all partners involved, for their support in the situation," the airline tweeted.

An Air India relief flight departed from the Russian airport at 12:02 am on Saturday, the airline stated.After the flight took off, the Indian Embassy

in Moscow thanked Russia's Foreign Ministry and others for the assistance provided to the stranded passengers.Taking to X, the Indian Embassy stated, "Air India Rescue Flight AI 1179 with passengers of AI-183 took off from Krasnoyarsk for San Francisco.".

The Embassy of India, Moscow, thanks the Foreign Ministry of Russia and its Representative Office in Krasnoyarsk, the Russian Federal Agency for Air Transport, the Krasnoyarsk Krai Government, airport authorities, and security officials for their assistance to the passengers and to the Embassy's team in the coordination work throughout the emergency situation," the Embassy added.Earlier on Friday, Air India obtained the regulatory clearance for the relief flight from Mumbai to fly US-bound flight passengers who were stranded at Krasnoyarsk International Airport (KJA).The airline stated that they were carrying essentials and sufficient food for all the stranded passengers.The San Francisco-bound Air India flight from Delhi was diverted to Russia on Thursday after the crew detected a potential issue in the cargo hold area.

Three Indian Coast Guard Ships Battle Cargo Ship Fire In Arabian Sea

New Delhi: The Indian Coast Guard said on Saturday that its three ships were battling a major fire aboard a cargo vessel in the Arabian Sea after responding to a distress call a day earlier.The vessel MV Maersk Frankfurt reported explosions on its front deck on Friday, 12 kilometres south of Karwar while sailing from India's Gujarat state to Colombo in Sri Lanka.

NO CASUALTIES

"Ships Sujeet, Sachet and Samrat have been fighting the fire for over 12 hours, preventing its spread," the India Coast Guard said in a statement Saturday posted on social media platform X. It posted images and videos showing the firefighting effort. No casualties were reported from the merchant vessel.

The Indian coast guard said a Donier aircraft was conducting aerial assessments and that an additional plane was also in position for search and rescue. The coast guard said

another ship was also despatched from Mumbai and likely to join the effort by Sunday.

On Saturday morning, the ICG said on its X handle, "Ships Sujeet, Sachet and Samrat have been fighting the fire for over 12 hours, preventing its spread. As of 0700 hrs, 20 Jul, the vessel is 6.5 NM south of Karwar." ICG's Dornier aircraft is conducting aerial assessment, with an additional aircraft from Kochi positioned for the search and rescue operation, it said."ETV Water Lily departed #Mumbai on 19 Jul, arriving on scene by 21 Jul," it added. The merchant vessel, on its way from Mundra to Colombo, was reportedly carrying "International Maritime Dangerous Goods (IMDG) cargo" and explosions have been occurring on its front part, the ICG had said on Friday.

On Wednesday the Indian navy rescued nine crew members and recovered one body from the Comorian-flagged MV Prestige Falcon oil tanker that had capsized off the coast of Oman earlier this week.

Exponential' Surge in Dengue Cases in South India; More Patients Coming in With Severe Complications Like Low BP

New Delhi: India has started experiencing a significant surge in dengue cases, particularly in the southern states. From witnessing up to 10 patients every day to 200 patients now, the extent of the surge in cases varies from state to state and city to city.While Delhi-NCR is noticing a mild surge, Mumbai and Kolkata are witnessing a moderate spike and southern cities and states are reporting a big jump.

The uptick in cases has been observed since the onset of the monsoon season, which typically exacerbates mosquito-borne diseases due to increased breeding sites for mosquitoes.According to several doctors News18 spoke to, the symptoms of dengue remain consistent with previous years, but they are observing an increase in cases with severe complications, specifically low blood pressure. Also, many patients – ranging between 20% to 50% of OPD cases – are requiring hospital admission.The top symptoms include high fever, severe headache, pain behind the eyes, joint and muscle pain, rashes and mild bleeding. Experts explain that these symptoms typically emerge 4-10 days after a mosquito bite and can last between two to 10 days.

ZOOMING CASES IN SOUTH INDIA

Dr K Somnath Gupta from Yashoda Hospitals, Hyderabad, told News18 that he has been seeing 200 cases of dengue per week as of early July 2024. "The severity of cases varies, but a substantial number of patients require hospitalisation. In Karnataka, about 20-30% of reported cases need admission due to severe symptoms or complications."Gupta believes that, this year, the frequency and severity of the disease has increased due to higher transmission rates. "The current outbreak has seen an uptick in severe cases and complications, potentially due to the co-circulation of multiple dengue serotypes."As per the state government data, over 9,000 dengue cases and seven deaths have been reported in Karnataka from January to July this year. Until July 13, 66,298 people were tested for dengue, out of which, a total of 9,082 people tested positive for the fever.However, the actual figures are estimated to be "at least three times the number", Dr L Sudarshan Reddy, senior consultant physician at Yashoda Hospitals, told News18. He said that "repeat infections tend to be more severe and often require hospitalization".

Similarly, Dr Sheela Chakravarthy, Director of Internal Medicine, Fortis Hospital, Bannerghatta Road, Bengaluru, said that she sees five to six dengue cases every day, with two to three patients requiring admissions, which means that almost half of the OPD patients require admission."Presently, we have 18 admitted patients, including one critical case. Notably, the number of cases has increased over the past week," she said.Chakravarthy highlighted that patients must be examined for danger signs such as low blood pressure and advised people to keep that in check while they are being treated in a home setting.Dr Tharanath S, infectious diseases specialist at Sparsh Hospital, Yelahanka, Bengaluru, calls the jump in cases over the past month "exponential".

"Between July 1 and July 19, our OPD has seen nearly 100 cases with clinical symptoms similar to dengue, of which 30% required admission for further medical management due to severe symptoms.""While the symptoms of dengue are consistent with the previous years, we are noting an increase in cases with severe complications such as low blood pressure."

DENGUE STATUS IN DELHI-NCR, KOLKATA & MUMBAI

In July, doctors in Delhi-NCR started noticing a mild surge with up to five patients in their OPDs every day and some patients requiring admission as well."Over the past week, our hospital has seen an average of 2-3 dengue patients per day.

Since July 1, we have noticed a sharp increase in cases, with around 10-12 severely affected patients requiring hospital admission due to severe symptoms such as low platelet counts and severe dehydration," Dr Gaurav Jain, senior consultant, Internal Medicine, Narayana Super Speciality Hospital, Dharamshila, New Delhi.

NEWS BOX

Sheila Lee Jackson, strong democratic voice in US Congress, dies at 74

Washington. US Representative Sheila Jackson Lee, a strong progressive voice in the Democratic Party who was outspoken on African-American and women's rights, has died, her family posted, on X late on Friday.

Jackson Lee of Texas announced last month she had been diagnosed with pancreatic cancer and was undergoing treatment. She was 74, according to US media."A fierce champion of the people, she was affectionately and simply known as 'Congresswoman' by her constituents in recognition of her near-ubiquitous presence and service to their daily lives for more than 30 years," her family said in the statement.Jackson Lee, who represented parts of Houston, introduced legislation in the House of Representatives to make "Juneteenth" a federal holiday commemorating the end of the legal

enslavement of Black Americans.

The holiday marks the day in 1865 when a Union general informed a group of enslaved people in Texas that they had been made free two years earlier by President Abraham Lincoln's Emancipation Proclamation during the Civil War.

We are going to win: Kamala Harris reassures worried Democratic donors

Washington. US Vice President Kamala Harris assured major Democratic donors on Friday that the party would win the presidential election as more lawmakers called for her running mate, President Joe Biden, to stand down.

"We are going to win this election," she said on a call arranged on short notice to calm donors, according to a person on the call. "We know which candidate in this election puts the American people first: Our president, Joe Biden."The call came after Biden vowed to continue in the 2024 race and the Democratic Party planned to accelerate his nomination. At least nine Democratic lawmakers called on Biden to drop out on Friday.Reuters reported that several of Biden's campaign fundraisers were put on hold, citing multiple Democratic sources involved in the events, as donors threatened to withhold funds from the campaign.

Donors were called to join the 30-minute briefing "to discuss urgent, emerging needs," according to a copy of

the invitation seen by Reuters.

Harris attended the call "at the direct request of senior advisers to the president," one of the people said, an account confirmed by another person familiar with the matter.

Bangladesh soldiers out in force as PM cancels foreign trip

DHAKA. Soldiers were out in force Saturday in cities around Bangladesh after another day of lethal clashes between student protesters and police prompted Prime Minister Sheikh Hasina to cancel foreign visits.

This week's violence has killed at least 105 people so far, according to an AFP count of victims reported by hospitals, and poses a significant challenge to Hasina's autocratic government after 15 years in office.A government curfew went into effect at midnight and the premier's office asked the military to deploy troops after police again failed to subdue mayhem."The government has decided to impose a curfew and deploy the military in aid of the civilian authorities," Hasina's press secretary Nayeemul Islam Khan told AFP.Streets of the capital Dhaka were almost deserted at daybreak, with troops on foot and in armoured personnel carriers patrolling the sprawling megacity of 20 million.Several rickshaw drivers downtown who ignored the curfew were told by police to return home.The curfew will remain in effect until 10:00 am (0400 GMT) Sunday, private broadcaster Channel 24 reported.Hasina had been due to leave the country on Sunday for a planned diplomatic tour but abandoned her plans after a week of escalating violence."She has cancelled her Spain and Brazil tours due to the prevailing situation, her press secretary Nayeemul Islam Khan told AFP.

Near-daily marches this month have called for an end to a quota system that reserves more than half of civil service posts for specific groups, including children of veterans from the country's 1971 liberation war against Pakistan.Critics say the scheme benefits children of pro-government groups that back Hasina, 76, who has ruled the country since 2009 and won her fourth consecutive election in January after a vote without genuine opposition.Hasina's government is accused by rights groups of misusing state institutions to entrench its hold on power and stamp out dissent, including by the extrajudicial killing of opposition activists.Police fire was the cause of more than half of the deaths reported so far this week, based on descriptions given to AFP by hospital staff."The rising death toll is a shocking indictment of the absolute intolerance shown by the Bangladeshi authorities to protest and dissent," Babu Ram Pant of Amnesty International said in a statement.Authorities imposed a nationwide internet shutdown on Thursday which remains in effect, severely hampering communication in and out of Bangladesh.

Israel threatens retaliation for Yemen rebel drone strike that killed 1

Tel Aviv. Israel threatened reprisals Friday after a drone claimed by Yemen's Huthi rebels penetrated its vaunted air defences and killed a civilian in a Tel Aviv apartment building near a US embassy annexe.

The attack drew condemnation from UN chief Antonio Guterres and an appeal for "maximum restraint" to avoid "further escalation in the region".

The pre-dawn strike came hours before Israel suffered another blow, a ruling by the UN's top court that its occupation of the Palestinian territories was "illegal" and needed to end as soon as possible.The advisory opinion of The Hague-based International Court of Justice is not binding, but it comes amid mounting international condemnation of Israel's handling of its war on Hamas in Gaza.The office of Palestinian president Mahmud Abbas hailed the court's decision as "a victory for justice". Hamas said it puts "the international system before the imperative of immediate action to end the occupation".But Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has overseen a major expansion of Jewish settlements in the occupied West Bank, insisted: "The Jewish people are not occupiers in their own land."The Huthis are one of a number of Iran-backed armed groups around the Middle East that have claimed drone and missile attacks on Israel in retaliation for the Gaza war.The group, which controls swathes of Yemen, including much of its Red Sea coast, has previously claimed attacks on Israeli cities including Ashdod, Haifa and Eilat, but Friday's strike appears to be the first to breach Israel's sophisticated air defences.The Huthis fired at Tel Aviv a "new drone called 'Yafa', which is capable of bypassing the enemy's interception systems", their spokesman Yahya Saree said.An Israeli military official, who spoke on condition of anonymity, said a "very big drone that can travel long distances" was used in the 3:12 am (0012 GMT) attack.He said the drone was detected but due to "human error" the alarm was not raised in time, and it slammed into an apartment building.Military spokesman Daniel Hagari said Israel believed the drone used was Iranian-made and upgraded so it

could reach Tel Aviv from Yemen -- at least 1,800 kilometres (1,100 miles) away.

Medical services said one civilian was killed and four people suffered "relatively minor" injuries.Defence Minister Yoav Gallant vowed revenge."The security system will settle the score with all who try to harm the state of Israel, or sends terrorism against it, in a decisive and surprising manner," he said in comments posted on social media platform X.

'Everything blew out'

In grainy security camera footage, the buzz of what appeared to be the drone was followed by an explosion that shook the building and set off car alarms.

The blast occurred about 100 metres (yards) from a US embassy annexe, said an AFP journalist who saw broken windows along the street lined with apartment blocks."It woke me up because the vibration of the sound was like a 747 (jet) coming in," said Kenneth Davis, an Israeli who was staying in a hotel opposite the building which was hit.And then the explosion... everything blew out in the room," he told AFPTV.Since November, the Huthis have also carried out dozens of drone and missile attacks on shipping in the Red Sea and Gulf of Aden that they claim is Israeli-linked.The United States and Britain launched a campaign of air strikes in January to deter the attacks on shipping.The Gaza war was triggered by Hamas's October 7 attack on Israel which resulted in the deaths of 1,195 people, mostly civilians, according to an AFP tally based on Israeli figures.The militants also seized 251 hostages, 116 of whom are still in Gaza, including 42 the Israeli military says are dead.Israel's retaliatory campaign has killed at least 38,848 people in Gaza.

Joe Biden vows re-election bid campaign despite increasing Democratic pressure

New Delhi. US President Joe Biden on Friday vowed to continue his campaign for re-election even as more fellow Democrats in Congress urged him to end his floundering campaign. His statement came after reports said that he was considering dropping out of the race."Together, as a party and as a country, we can and will defeat him at the ballot box," Biden said. "The stakes are high, and the choice is clear. Together, we will win," Biden said."I look forward to getting back on the campaign trail next week to continue exposing the threat of Donald Trump's Project 2025 agenda while making the case for my own record and the vision that I have for America," he said in a statement, referring to a policy plan developed by Trump's conservative allies.Media reports also said Biden's family members have begun contemplating what the latter's exit from his floundering campaign would look like.According to news agency Reuters, more than one in 10 congressional Democrats have now publicly called on Biden to drop out.

However, Biden, who has insisted he can

beat Republican Donald Trump, remained defiant, saying he would resume campaigning soon.

Biden, 81, tested positive for Covid-19 while travelling in Las Vegas earlier this week and experienced "mild symptoms" including "general malaise" from the infection, the White House said.His disastrous June debate against Trump raised questions about his ability to win or to carry out his duties for another four years.

So far, 32 of the 264 Democrats in Congress have openly called for Biden to end his campaign, while other senior Democratic leaders have pushed him behind the scenes to do so, Reuters quoted sources and media reports.Democrats are increasingly worried about a Republican sweep in the November 5 election that could leave Trump and his allies not only in charge of the White House but also with majorities in both chambers of Congress.

Among the democrats expressing worries to allies about Biden's chances were former President Barack Obama and Speaker Emerita Nancy Pelosi, who has privately told Biden the party could lose the ability to seize control of the House if he doesn't step aside.New Mexico Senator Martin Heinrich called on Biden to exit the race, making him the third Senate Democrat to do so.Amid the turmoil, a majority of Democrats think Vice President Kamala Harris would make a good president herself.

In call with Ukrainian President, Donald Trump pledges to end Russia war

World US Republican presidential candidate Donald Trump on Friday spoke to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, pledging to end the European country's war with Russia.

In a post on his Truth Social platform, Trump wrote, "I appreciate President Zelensky for reaching out because I, as your next President of the United States, will bring peace to the world and end the war that has cost so many lives and devastated countless innocent families."

"Both sides will be able to come together and negotiate a deal that ends the violence and paves a path forward to prosperity," he added.Later, in an X post, the Ukrainian President acknowledged his conversation with Trump and said, "I spoke with Donald Trump to congratulate him on the Republican nomination and condemn the shocking assassination attempt in Pennsylvania. I wished him strength and absolute safety in the future.""I noted the vital bipartisan and bicameral American support for protecting our nation's freedom and independence. Ukraine will always be grateful to the United States for its help in

strengthening our ability to resist Russian terror. Russian attacks on our cities and villages continue every day.""We agreed with President Trump to discuss at a personal meeting what steps can make peace fair and truly lasting," Zelenskyy tweeted.

RUSSIA-UKRAINE WAR

The United States has provided tens of billions of dollars in military assistance for Kyiv since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine in February 2022 -- though a Trump victory in the November election would put Washington's continued support into question.Trump's running mate JD Vance leads the isolationist wing of congressional Republicans, who argue the United States should drop aid to Ukraine.

Vance was one of the fiercest opponents of the approval of $61 billion in new military aid for Ukraine, which was stalled by Republican lawmakers for months earlier this year -- a time in which Russia made battlefield gains.Trump told the Republican National Convention in Milwaukee on Thursday that he would bring an end to raging international crises.

Usha Chilukuri Vance's granduncle, an RSS worker, was jailed during Emergency

World Usha Chilukuri Vance, the wife of Donald Trump's running mate JD Vance, has gained significant attention for her Indian roots. One of her close relatives was a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) worker and was jailed during the Emergency in India."Usha is the granddaughter of Ramasastry, my husband Subramanya Sastry's eldest brother. My husband spent two years in jail during the Emergency as he was an RSS worker," Shanthamma Chilukuri, Usha's great-aunt, told The Times of India.The Emergency in India was a 21-month period from 1975 to 1977. Then Prime Minister Indira Gandhi had suspended rights and jailed opposition leaders and activists.Her great-aunt Shanthamma, at 96, is India's oldest active professor, travelling 60 km daily to teach physics at a university in Visakhapatnam.

Usha, 38, is the daughter of Indian immigrants who moved to the US in the late 1970s. She practices Hinduism and has an impressive academic background, having studied at Yale and Cambridge.She previously worked as a law clerk to US Chief Justice John Roberts and later as an attorney at Munger, Tolles & Olson LLP.JD Vance said that Usha, a practising Hindu, helped him find his Christian faith.Shanthamma Chilukuri told Reuters that many in the family were well-versed in ancient texts like Upanishads and Vedas. She has authored a book on verses from the Bhagavad Gita.

The Chilukuri family places a strong emphasis on education, with Usha's father and grandfather associated with the Indian Institute of Technology (IIT)."Most of our family is academically strong and education has been a top priority," Chilukuri told Reuters.The family hails from Vadduru in Andhra Pradesh but moved to Chennai when Usha's grandfather, Ramasastry Chilukuri, joined the Indian Institute of Technology (IIT) in 1959.The IIT now runs a student award in the memory of Ramasastry, who used to teach physics, reported Reuters.

Usha's introduction of her husband at the Republican National Convention in Milwaukee marked her debut on the US national political stage.If Trump wins the upcoming elction which is going to be held in November, Usha could become the 'Second Lady' of the United States.The Emergency in India was a period when Prime Minister Indira Gandhi declared a state of emergency, leading to the arrest of many opposition leaders and RSS workers.

40 Haitian migrants die after voodoo ritual sets boat on fire

At least 40 migrants have died after a boat they were travelling in caught fire off the northern coast of Haiti. As per a UN agency, the explosion was sparked by a voodoo ritual gone wrong.

Port-au-Prince, Haiti. At least 40 migrants have died after a boat they were travelling in caught fire off the northern coast of Haiti, a UN agency said Friday, with police saying the explosion was sparked by a voodoo ritual gone wrong.The UN's International Organization for Migration (IOM) reported that the Haitian Coast Guard rescued 41 survivors, 11 of whom were hospitalized, including some for burns.

But "at least 40 migrants have died, and several others were injured," the IOM said.The fire began when a passenger lit a candle to start a voodoo ritual, police spokesperson Arold Jean said.Survivors told local media that the voodoo ceremony was meant to bring luck and help the boat avoid being intercepted by the coast guard."This devastating event highlights the risks faced by children, women and men migrating through irregular routes," said Gregoire Goodstein, IOM's chief of mission in the country.The boat, carrying more than 80 people, had left the port of Labadee on Wednesday en route to the Turks and Caicos Islands, a 150-mile (240-kilometer) journey, the IOM reported, citing Haiti's National Office for Migration."The search continues with the aim of finding other survivors," said Jean, adding that an investigation had been opened to "identify and dismantle the networks that organize these clandestine voyages."Migration from the poorest country in the Americas has been surging for months, as thousands of people flee a spike in violence from criminal gangs that now control wide swaths of territory.

The gangs have attacked prisons, destroyed dozens of police stations, and invaded the main airport, with the government's hold over the country tenuous."Haiti's socioeconomic situation is in agony," Goodstein said. "The extreme violence over the past months has only brought Haitians to resort to desperate measures even more."Hundreds of police officers from Kenya have been deployed in Haiti's capital Port-au-Prince, part of an international effort to bring stability to a country riven by political, social and economic chaos.Newly named Prime Minister Gary Conille, a former UN official, has welcomed the Kenyan contingent and vowed to launch a police operation against the gangs.Criminal groups control 80 percent of the capital city, with residents saying they have faced the threat of murder, rape and kidnapping for ransom.As the pace of emigration grows, Haitian Coast Guard units in the north have observed an increasing number of departures by boat, the IOM said.Countries including the United States, the Bahamas, the Turks and Caicos Islands, and Jamaica say they have intercepted a growing number of boats originating from Haiti.More than 86,000 migrants have been forcibly returned to Haiti by neighboring countries this year, according to the IOM.

The country currently has nearly 600,000 internally displaced people, according to UN figures, a 60 percent increase since March.

NEWS BOX

Neeraj Chopra's consistency has brought him success: AFI chief Adille Sumariwalla

New Delhi. Athletics Federation of India chief Adille Sumariwalla heaped praise on Neeraj Chopra for bringing laurels for India by showing unreal consistency in the javelin throw. Neeraj is all set to defend in crown when the Paris Olympics gets underway on July 26. Back in 2021, he won the gold medal and became India's first track and field athlete to do so in the quadrennial event.

Neeraj has not looked back since then and has only grown in stature, winning medals in tournaments around the world. Sumariwalla said that Chopra is not someone who would dwell on the past and would rather live in the present."Neeraj is the person who lives in the moment. Other people think about past, future but Neeraj lives in the present. That is why he is so successful. He knows 'I have to do this much'. Whenever you ask him to throw, he will always do 88-89 metres; that is his consistency. His consistency has got him all the victories," Sumariwalla said at a promotional event, as quoted by PTI.

Neeraj Chopra earns praise for grit and determinationBack in the 2022 Stockholm Diamond League, Chopra threw 89.94 metres, his best throw until now. Although he is yet to touch the elusive 90-metre mark, Sumariwalla said that it has hardly made a difference to Neeraj winning tournaments consistently.Last Olympics, three people had 90m-plus throws, Neeraj won in 88m (87.58), Before the World Championships (2023 Budapest), there were three people who threw 90-plus, Neeraj won in 89 (88.17m). Before the Asian Games in Hangzhou, there was one guy who was throwing over 90, Neeraj won gold. So, on that day what happens can be very different. There are people who have crossed 90m and Neeraj has never crossed 90m, but he won every time," Sumariwalla added.

Neeraj has had a decent year until now. He won the gold medal in the Federation Cup with a throw of 82.27 metres. Back in May, he finished second in the Doha Diamond League with a best attempt of 88.36 metres.

Mohammad Shami recalls missing 2019 WC semis: What more do you expect from me

New Delhi Fast bowler Mohammed Shami recalled the times when he did not play in the semi-final of the ODI World Cup in 2019 despite being one of India's standout bowlers in the tournament. Shami picked up 14 wickets from four matches at an excellent economy rate of 5.48.Shami picked up a five-wicket haul against England and rattled Afghanistan with a hat-trick. But the Men in Blue left him out of the team in the semis against Kane Williamson's New Zealand at Old Trafford in Manchester. India lost the match by 18 runs after failing to chase down 240."In 2019, I did not play the first 4–5 games. In the next game, I took a hat-trick, then picked up a five-wicket haul and then four wickets in the next game. A similar thing happened in 2023. I did not play in the first few games and then picked a fifer, then four wickets and then a five-wicket haul again," Shami told Shubhankar Mishra on the latter's YouTube show 'Unplugged'."The one thing I keep wondering is every team needs players who can perform well. I took 13 wickets in three matches. What more do you expect from me? I neither have questions nor do I have answers."

'I can only prove myself'

Shami was the top wicket-taker in the ODI World Cup 2023, where India finished as the runners-up after losing to Australia in the final at the Narendra Modi Stadium. Shami picked up 24 wickets from seven games with three five-wicket hauls to show for his efforts.I can only prove myself when I get the opportunity. You gave me a chance, and I took 13 wickets in three matches. Then we lost to New Zealand. Played four matches overall and picked 14 wickets. In 2023, I picked 24 wickets in seven matches," Shami added.Shami hasn't played competitive cricket since the World Cup final last year. He has undergone surgeries and also missed playing for GT in the Indian Premier League (IPL) 2024. Shami has returned to bowling in the nets, but there is no official confirmation on his return.

Paris Olympics: Lakshya Sen aims to be 'really sharp' in tough pool at big stage

New Delhi Lakshya Sen is wary of the tough challenge that lies ahead of him in the Paris Olympics 2024. Set to make his debut at the quadrennial event, the youngster knows that the pool he is in where the likes of World No.3 Jonatan Christie, World No.41 Kevin Cordon and World No.52 Julien Carraggi feature.While a player of Lakshya's calibre is expected to beat Cordon and Carragi, his biggest test lies in the form of Christie, who has made him sweat in their previous meetings. Christie has a 4-1 lead over Lakshya on the head-to-head count."Christie has been a tough opponent. All my matches against him have been close. I will be watching those matches, observing the areas I can do better from last time. Simultaneously, I'll be focussing on my strengths, on how I can control the game and play my best," Lakshya told Hindustan Times.

'Biggest tournament of my life'

Back in 2022, Lakshya won gold at the Commonwealth Games in Birmingham. But the Olympics is expected to be a different ballgame altogether. The 22-year-old said the Olympics will be the "biggest tournament of my life" until now."I have played all of them before. I know what to expect. It is a tough pool. But I would be playing the Belgian and Guatemalan before facing Christie which will help me set up a good match against Christie.

UEFA launches disciplinary investigation on Morata and Rodri for Euro 2024 chants

Spain skipper Alvaro Morata and Rodri have the chances of getting handed a two-match ban after UEFA launched a disciplinary investigation on both for their chants about Gibraltar after their Euro 2024 celebrations. The Spanish duo sang chants on Gibraltar being a part of Spain and not the UK.

New Delhi. Spain's Alvaro Morata and Rodrigo Hernandez face the threat of being banned for two matches by UEFA after a disciplinary investigation was launched against the duo for their chants about Gibraltar during their Euro 2024 title celebrations this week. Spanish skipper Morata and Euro 2024 Player of the tournament midfielder Rodri might be slammed with a heavy punishment for singing chants about Gibraltar being a part of Spain and not the UK.

After clinching what was their fourth European Championship by beating England in the Euro 2024 Final by 2-1 on July 14, the entire Spanish team travelled to Madrid on Monday to celebrate their title with their home fans. Both Morata and Rodri were spotted singing the chants about Gibraltar, which according to UEFA's statement, falls beyond the body's disciplinary parameters. The Gibraltar FA had also released a statement condemning the actions of the Spanish duo and lodging a complant to UEFA for the same.

" The Gibraltar FA has noted the extremely provocative and insulting nature of the celebrations around the Spanish Men's national team winning Euro 2024. The Association is this morning taking advice on the filing of a complaint to European Football's governing body, UEFA, in relation to the unacceptable chanting and songs, relating to Gibraltar, sung by Spain's Men's National Team players after winning Euro 2024. Football has no place for behaviour of this nature," the statement from Gibraltar FA read."A UEFA Ethics and Disciplinary Inspector is being appointed to evaluate a potential violation of the Uefa Disciplinary Regulations by the players Rodrigo Hernández Cascante and Ivaro Morata in the context of conduct that occurred during the public presentation of the UEFA Euro 2024 trophy in Madrid on 15 July 2024. Further information regarding this matter will be made available in due course," UEFA's statement read.In case both Morata and Rodri are declared guilty after the investigation, the Spanish duo has the chances of being handed a minimum of two games ban by the UEFA governing body. Rodri will be travelling back to England to join the rest of his Manchester City squad for pre-season, Morata will be starting his new chapter at AC Milan after making a move away from his former La Liga side Atletico Madrid.

24 Service personnel among 117 Indian athletes taking part in Paris Olympics 2024

New Delhi. 24 armed-forces personnel are amongst the 117 Indian athletes who are all set to make the nation proud at the Paris Olympics, beginning July 26, 2024. Among these 24 athletes, 22 are men, including star Javelin thrower Subedar Neeraj Chopra, and two are women, which marks the maiden participation of female Service athletes at the Olympics.

Subedar Neeraj Chopra, the 2020 Tokyo Olympics Gold medallist, will again vie for top honours as his participation in the Paris Olympics comes on the back of exceptional performances which earned him a gold medal each at the 2023 Asian Games, 2023 World Athletics Championship, 2024 Diamond League, and 2024 Paavo Nurmi Games.2022 Commonwealth Games bronze medalist Havildar Jaismine Lamboria and 2023 Asian Wrestling Championships bronze medalist CPO Ritika Hooda are the two women service personnel who are taking part in the Games for the first time, and would aim to create history. They will feature in Boxing and Wrestling respectively.

Sub Amit Panghal (Boxing); CPO Tajinderpal Singh Toor (Shot-Put); Sub Avinash Mukund Sable (3000m Steeplechase); CPO Muhammed Anas Yahiya, PO (GW) Muhammed Ajmal, Sub Santhosh Kumar Tamilarasan & JWO Mijo Chacko Kurian (4X400M Men's Relay); JWO Abdulla Aboobacker (Triple Jump); Sub Tarundeep Rai & Sub Dhiraj Bommadevara (Archery) and Nb Sub Sandeep Singh (Shooting) are also among the Service personnel who would aim to bring laurels to the country.

Mohammed Shami slams Inzamam-ul-Haq for 'cartoongiri' after dig at Arshdeep Singh

New Delhi Mohammed Shami has slammed Inzamam-ul-Haq after the former Pakistan captain questioned Arshdeep Singh for getting reverse swing during the T20 World Cup 2024. After India's match against Australia in the Super 8, Inzamam claimed it's tough for a bowler to generate reverse swing as early in the 14th or 15th over in a match.

Although it was Rohit Sharma who won the Player of the Match award, Arshdeep also collected accolades for picking up three crucial wickets of David Warner, Tim David and Matthew Wade. On the back of his spell, India successfully defended 205 and won by 24 runs. Shami opened up while speaking on Shubhankar Mishra's YouTube channel."I have said in an interview that I will cut the ball and show if there is a device or not. Abhi ek aur namuna khod ke dia hai inhone. They said, 'How can Arshdeep Singh get reverse swing?' I want to say only one thing to Inzamam bhai. I respect him a lot. If you do the same thing, isn't it ball-tampering? Those who do well against them, will be their target. India and Pakistan are arch-rivals," Shami said.

These statements are there to fool people'

Shami asked former Pakistan cricketers to not try and fool people by making bizarre claims. The speedster also supported the legendary Wasim Akram, who said last year that balls do not have devices and there is no question of taking any undue advantage.

Mohammed Shami said that the claims made by former Pakistani cricketers, including Inzamam-ul-Haq, that Indian bowlers get reverse swing through pre-planning, are bizarre.

"I don't expect that despite being ex-players you can say such thing. Even Wasim Akram said how umpires give you the ball and it is not possible to plant any device in it. This type of cartoongiri is not good. These statements are there to fool people," Shami added.

Arshdeep was India's standout bowler and finished as the second-highest wicket-taker of the tournament with 17 scalps to his name from eight matches at an economy rate of 7.61. He also picked up a four-wicket haul against the United States.

Kavem Hodge 'happy, satisfied' after maiden Test hundred vs ENG: Dream comes true

New Delhi. Kavem Hodge was over the moon after he racked up his maiden Test century in trying times against England at Trent Bridge in Nottingham. Hodge found the right balance between attack and defence as he got to his three-figure score off 143 balls on Day 2 of the second Test. Batting at No.5, Hodge made sure that the hosts did not run away with the match after putting on 416 in the first innings.

Just when it seemed that Hodge would play until the end of the day, Chris Woakes trapped him in front to cut short his stay in the middle. He scored 120 runs off 171 balls with 19 fours before getting out. The right-hander was satisfied after being able to stand out for his team in a crisis.

ENG vs WI Day 2 Highlights

"It's a dream come true, you play the game as a youngster, that's something that you want to do, especially at the highest level - in England against England. I'm really happy and satisfied about it, especially also the position of the team, it's always good to help the team's cause," Hodge said at the end of the day's play.

'Tend to go under the radar'

After West Indies lost the quick wickets of Mikyle Louis, Kraigg Brathwaite and Kirk McKenzie, Hodge joined hands with Alick Athanaze and put on a handy partnership of 175 runs for the fourth wicket. Hodge said that they complemented each other well.

"We always bat good together, play for the same franchise back home, we've had a lot of big partnerships. He's more aggressive than I am, I'm more of an accumulator, so I tend to go under the radar and go about my business quietly. Always good to spend time with him at the wicket," Hodge added.

Hodge's knock ensured that West Indies got the deficit down to 65 runs in their first innings after being at 351 for the loss of five wickets. Jason Holder and Joshua Da Silva played out the remaining 9.4 overs of the day after Hodge departed.

Did You Know Who is India's oldest and youngest athlete at Paris Olympics

At 44, Rohan Bopanna will be India's oldest athlete at the Paris Olympics. At 14, Dhinidhi Desinghu will be the youngest athlete in Paris, competing in women's 200m freestyle event.

New Delhi India will head into the Paris Olympics with a 117-strong contingent, four shy of the record tally from 2021. The hopes of breaching the best-ever mark of seven are ever-so high as the Indian contingent has headed to the city of romance with a lot of success over the last three years.India has a good mix of experience and youth in almost every discipline. At 44, tennis ace Rohan Bopanna is the oldest athlete in the Indian contingent for the Paris Olympics. At 14, Dhinidhi Desinghu is the youngest athlete in the Indian contingent.

ROHAN BOPANNA: INDIA'S OLDEST ATHLETE AT PARIS OLYMPICS

Bopanna will return to give winning an Olympic medal another shot at Paris. This will be the senior campaigner's third appearance in the Olympics. Bopanna and Mahesh Bhupati paired together in 2012 and reached the second round of the men's doubles competition.

Paris Olympics: Full Coverage

In 2016, Bopanna and Leander Paes paired for the men's doubles event, but bowed out in the opening round. However, Bopanna and his mixed doubles partner Sania Mirza nearly brought home a medal. The mixed doubles pair lost the bronze medal match to Lucie Hradecka and Radek Stepaneck of the Czech Republic in straight sets.

While Bopanna did not qualify for the Tokyo

Olympics, the 44-year-old, who has been ageing like fine wine, secured the quota for India via his ranking on the tour - World No. 4. The Karnataka tennis great will partner with World No. 62 N Sriram Balaji. Bopanna is heading into the Olympics on the back of a sensational run on the tour. He became the oldest World No. 1 earlier this year and also became the oldest man to win a Grand Slam crown when he and his Australian partner Matthew Ebden won the Australian Open crown. They also reached the men's doubles semi-final at Roland Garros.Bopanna and Balaji's first outing as a pairing in 2024 did not go according to plan as they were knocked out in the first round of the Hamburg Open, an ATP 500 tournament on clay.

DHINIDHI DESINGHU: INDIA'S YOUNGEST AT PARIS GAMES

Dhinidhi Desinghu, a 14-year-old swimmer from Bengaluru, is set to make history as India's youngest athlete at the 2024 Paris Olympics. This remarkable achievement comes after she was awarded the Universality quota by the Olympic Games Tripartite Commission, alongside seasoned swimmer Srihari Nataraj.Desinghu will compete in the women's 200m freestyle event, making her the second youngest Indian Olympian in history, with Aarti Saha holding the record for the youngest Indian Olympian at the age of 11 in the 1952 Helsinki Olympics. Despite being only in the ninth grade in school.

Disha Patani

Aces Double Back-Flip In Latest Fitness Video: 'One Step At A Time'

Disha Patani is at it again with another fitness video. Known for inspiring her fans with her intense workout routines, the actress has made headlines with her latest Instagram post. In the new video, Disha performs back-flips with impressive precision, showcasing her fitness prowess. Her dedication and flawless execution have captivated viewers, making it hard to look away.Disha Patani left us all stunned with her fascinating show of strength, stamina and flexibility in the latest video. In the video, not only did she ace the difficult backflip but took it a notch higher. Depicting the constant growth, she later performed the double backflip, landing gracefully. We are impressed, Disha! The expressions of happiness as she effortlessly pulled off the task were too cute to ignore. Disha captioned her video, "One step at a time."

That's not the first time Disha Patani has treated us to a glimpse of intense physical training. In a video shared a few months back, Disha first effortlessly climbed on top of some floor mats stacked together only to perform a very difficult backflip. After successfully completing her mission, Disha was visibly brimming with joy.

Even other posts on Disha Patani's timeline are a peek into her workout routine. She loves spending her time in the gym. One of her rigorous workout routine videos depicted her lifting weights. She captioned it, "140 pounds (70 pounds each side)*4 reps 110 pounds (55 pounds each side)*10 reps #deadlift Strength training, and as you can see dying too#strongereveryday."

Work-wise, Disha Patani's last role was in Kalki 2898 AD co-starring Prabhas, Amitabh Bachchan, Deepika Padukone and Kamal Haasan among others. Released on June 27, the film has been going strong ever since, raking in nearly 1000 crores worldwide. That's not all. Fans have already begun waiting for its next installment as announced by the makers on various occasions.Next up for Disha Patani is Kanguva alongside Suriya, Bobby Deol and Prakash Raj. While Kanguva is set to be released on October 10 this year, the script for Kanguva Part 2 is currently in development and will go on floors in late 2025 or early 2026.

Trisha Krishnan

And Nayanthara Had A Fall Out? What We Know

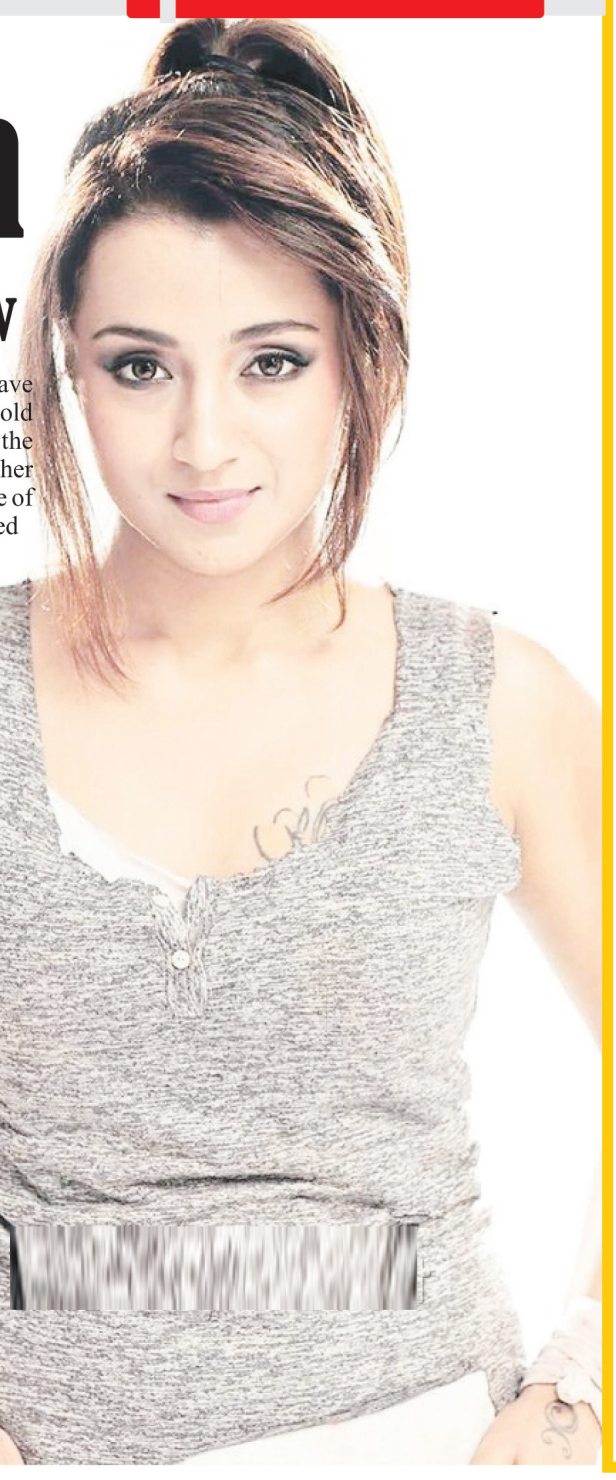

Popular actresses Trisha Krishnan and Nayanthara were known to have a strong bond and friendship. Both actresses have been ruling the hearts of the fans for more than 20 years now. Both have a massive fanbase globally. However, some old reports suggest that the duo was not on talking terms. This was supposedly due to so professional reasons that the actresses decided to part ways.According to an old report from 2008, Trisha and Nayanthara had a clash with each other over the Tamil film Kuruvi. As per a report by the Times of India, both the actress were initially considered for the role of Devi in the film. Eventually, Trisha was chosen for the role. Despite this news of professional dispute being shared widely, Trisha denied these rumours in an interview with India Herald. Several media reports suggested that both actresses did not speak with each other for several years.

Recently, Trisha decided to respond to the speculation about her and Nayanthara's relationship. In the interview, she mentioned that most of the speculations were made up and there was no such issue between them. She agreed that though they had some tussle it was not regarding professional life. She said, "Nayad has more than 10 years of experience in the field of acting. Our problems were mostly made up by the media. We never fought. Yeah we had some minor falling out over shared acquaintances and personal issues."On the other hand, Nayanthara also commented on her relationship with Trisha. She mentioned that their long-term separation was caused by some misconceptions. While talking to the media, the actress appreciated Trisha for making the effort to solve the issues they had to date and mend the relationship between them. "There were some misunderstandings that affected our relationship. What more could I want for when she took the time to reach out to me? That's extremely appreciated," Nayanthara said.

Arjun Kapoor Drops Cryptic Post Amid Breakup Rumours With Malaika Arora: 'Staying Positive Does Not...'

Speculation of Arjun Kapoor and Malaika Arora's breakup has ignited considerable conversation across social media platforms. Although the couple has not directly addressed these rumors, they have subtly referenced their relationship status online. Arjun Kapoor recently shared a poignant note on Instagram, focusing on navigating through pain while maintaining a positive outlook.Arjun Kapoor took to his Instagram story to share an uplifting message which read, "Staying positive does not mean that things will turn out okay. Rather, it is knowing you will be okay no matter how things turn out." This inspiring note came shortly after another cryptic post by the actor, which stated, "We have two choices in life. We can be prisoners of our past or explorers of future possibilities."

Meanwhile, Malaika Arora has sparked dating rumours amid reports that she and Arjun Kapoor have broken up. The Chaiyya Chaiyya girl is holidaying in Spain currently and has been flooding our timelines with photos from the trip. While she has been raising temperatures with her bikini-clad photos, she is also devouring good food during the trip. Just a couple of days back, Maliaka seemingly shared a photo of a mystery man. In the photo, she was sharing a picture of a plate of clams, the beach view and a man whose face was blurred. The photo has sparked rumours that Malaika is dating again.couple since 2018. While they have largely kept their relationship private, they have shared glimpses of their time together through affectionate photos from vacations and heartfelt birthday wishes on social media. Malaika was previously married to Arbaaz Khan, with whom she has a son named Arhaan. The former couple finalized their divorce in May 2017, and Arbaaz recently remarried Sshura Khan.

Shalini Ajith Kumar's Heartwarming Picture With Son Aadvik Is Pure Mother-Son Goals

Actress Shalini Ajith Kumar has shared a heartwarming photo with her son Aadvik on Instagram. In the picture, Shalini is seen resting on her bed while Aadvik kisses her on the forehead. Shalini shared the photo with lots of heart emojis as she held her son close. This adorable mother-son moment has gone viral, with fans sending love and well-wishes for Shalini's good health. A person wrote, "Cutest picture of the day," while another noted, "Mother love."

Shalini Ajith Kumar recently underwent a minor surgery at a hospital in Chennai. Her husband and Tamil actor Ajith Kumar, who was working on his upcoming film Vivek Muyarchi in Azerbaijan, came back to the city to take care of her. On July 3, Shalini shared a photo from her hospital bed with Ajith Kumar. In the picture, Shalini is wearing a patient's gown while Ajith sits by her side. The couple held hands and smiled for the photo. Alongside the picture, Shalini wrote in the caption, "Love you forever."

According to a report by India Today, a source revealed that Shalini is now doing fine. "It's too personal, so let's not get into the details. But she underwent surgery and is doing fine now. There's a possibility that an official statement might be shared in a day or two," the source added.

Speaking of Ajith Kumar's upcoming film Vidaa Muyarchi, the shooting has been put on hold until the actor's returns. Directed by Magizh Thirumeni, the film is about a married couple whose trip takes a dark turn when the wife goes missing. The husband desperately searches for her while an unknown villain creates obstacles along the way. The film also features Priya Bhavani Shankar, Sanjay Dutt and Trisha Krishnan in pivotal roles.Shalini Ajith Kumar began her career as a child artist in 1983 in Malayalam film Ente Mamattikkuttiyammakku and acted in several films directed by Fazil. She is best known for her roles in Alaipayuthey (2000), Aniyathi Pravu (1997) and Amarkalam (1999).